राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 33 अंक 10 जनवरी 2012 नयी दिल्ली मूल्य 5 रु. पृष्ठ 32

गीता और गांधी के पुनर्स्मरण से विश्वगुरू वनेगा भारत : न्यायमूर्ति लाहोटी

व्यवस्था परिवर्तन ॥
चुनाव सुधार

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक
आशुतोष

सम्पादक मण्डल
अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन: 011-43098248
ईमेल: chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग: chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाइट: www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-५०, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली-०७ से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के. ३० नवीन शाहदरा, दिल्ली- ३२ द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय:
"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

अनुक्रमणिका

विषय	पृ.सं.
संपादकीय	04
सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है केंद्र सरकार - मराठे	05
गीता और गांधी के पुनर्स्मरण से विश्वगुरू बनेगा भारत - न्यायमूर्ति लाहोटी	06
वर्ष २०११ का प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार	10
स्वप्नभंग से भ्रम टूटा, अब नये तरीकों की खोज जरूरी - सुनील आंबेकर	11
महामंत्री प्रतिवेदन वर्ष २०१०-२०११	13
राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्ताव	17
गणित के जादूगर रामानुजन	25
वैश्विक है भारत की एकात्म शिक्षा प्रणाली - लक्ष्मीनारायण भाला	27

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57 वां राष्ट्रीय अधिवेशन 4–5–6 जनवरी 2012 को नयी दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इससे पूर्व वर्ष 1985 में अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष के अवसर पर दिल्ली में राजघाट पर 25 से 28 दिसम्बर तक परिषद का 31 वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। आध्यात्मिक विभूति स्वामी रंगनाथानंद की अध्यक्षता में सम्पन्न उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी अधिवेशन में विश्व विद्यार्थी युवा संघ (वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एण्ड यूथ) का भी गठन हुआ।

26 वर्ष बाद दिल्ली को एक बार पुनः अधिवेशन के आतिथ्य का अवसर प्राप्त हुआ। इस बीच युवा वर्ष अधिवेशन के आयोजन में जुटी टोली छात्र जीवन से निकल कर समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में पहुंची और उसने उपलब्धियों के अनेक कीर्तिमान गढ़े। नये दायित्वों के चलते उनकी व्यस्तता में वृद्धि हुई किन्तु परिषद के साथ उनका स्नेह और संवाद निरंतर बना रहा। इस वर्ष जब दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा प्रारंभ हुई तो सभी के मन में अतीत की स्मृतियां सजीव हो उठीं। तालकटोरा स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर एक छात्र–संगठन का अधिवेशन व्यवस्थाओं की दृष्टि से सरल न था। किन्तु अपने–अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार सभी कार्यकर्ताओं ने दायित्व ले लिये और अधिवेशन का वातावरण बन गया। वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के अनुभवी नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की वर्तमान टोली ने अथक परिश्रम करके अपने संगठन तंत्र को सशक्त किया और बैठकों में बनी योजना को धरातल पर उतार दिया। कार्यकर्ताओं की इस पीढ़ी के सम्मुख इतने बड़े आयोजन का यह पहला अवसर था किन्तु आयोजन को सफल बनाने में उनका योगदान निस्संदेह अभिनन्दनीय है।

एक ओर जहां व्यवस्था पक्ष बेहद मजबूत था वहीं दूसरी ओर विषय–वस्तु के स्तर पर भी यह अधिवेशन उल्लेखनीय था। पहली बार किसी अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर छः समान्तर सत्रों में विषय प्रवर्तन के लिये देश की नामचीन हस्तियां मौजूद थी। शोभायात्रा और खुला अधिवेशन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की योजना न होने के कारण भारत की विविधता के दर्शन का अवसर भले ही न मिल सका हो किन्तु उस समय का उपयोग जिस प्रकार गहन चिंतन के लिये किया गया, उसने अधिवेशन को अकादमिक ऊंचाई प्रदान की।

दिसम्बर 2010 में बेंगालुरू में सम्पन्न अधिवेशन में परिषद ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष की रूप–रेखा बनायी थी। गत संपूर्ण वर्ष संगठन की गतिविधियां भ्रष्टाचार को केन्द्रित कर चलीं। अनेक कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी हुए तथा देश भर में लाखों छात्र–युवाओं ने इनमें भाग लिया। दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत किये गये आन्दोलनात्मक वृत्त से स्पष्ट है कि संपूर्ण देश में अभाविप की भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन की पहल को पर्याप्त प्रतिसाद मिला है। आगामी वर्ष में भी संगठन ने अपनी इस मुहिम को जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। 2012 के अंत में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाले अगले राष्ट्रीय अधिवेशन तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध परिषद का यह संघर्ष कौन से नये पड़ाव पार करता है, यह तो समय ही बतायेगा।

सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है केंद्र सरकार - मराठे

"भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से खोखला कर देने वाले भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा करना जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हेतु लगातार संघर्ष कर रही है तथा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को व्यापक व परिणामकारी आंदोलन बनाने की रणनीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार की समस्या से निजात पाने के लिए जितने भी व्यक्तिगत व सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं उन्हें एक मंच पर आकर इसके विरूद्ध जंग छेड़ने की जरूरत है तभी भ्रष्टाचार से देश को छुटकारा दिलाया जाना संभव है।"

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे ने कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक के उद्घाटन के अवसर पर कहीं।

इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.मिलिंद मराठे तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने दीप प्रज्जवलित कर किया। 57वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि – "युवा शक्ति देश की समृद्धि देखना चाहती है,। इसलिए वह किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार व भ्रष्ट तंत्र की करतूतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त वर्तमान केन्द्र सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। विद्यार्थी परिषद अनुशासित तथा भव्य और समृद्ध भारत के निर्माण का स्वप्न देख रहे युवाओं की बदौलत व्यापक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लडेगी।"

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में 3 दिन तक चलने वाले अधिवेशन के विषयों व स्वरूप के बारे में विस्तृत चर्चा हुई तथा अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों – देश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, देश का वर्तमान परिदृश्य, चीन की विस्तारवादी नीति से उत्पन्न खतरे व भ्रष्टाचार को व्यापक चर्चा के पश्चात अंतिम रूप दिया गया। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार का विषय प्रमुख रूप से चर्चा का केन्द्र बिन्दु बना रहा। विद्यार्थी परिषद द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों की गहन समीक्षा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में विद्यार्थी परिषद् द्वारा शैक्षणिक परिसरों व शिक्षा क्षेत्रों में चले आंदोलनों, विशेषकर शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ हुए कार्यक्रम, देश-भर में विद्यार्थी परिषद् को छात्रसंघ चुनावों में मिली भारी सफलता, परिषद् के अन्य प्रकल्पों तथा विश्व युवा विद्यार्थी संगठन (WOSY) अंतर राज्य छात्र जीवन-दर्शन (SEIL), विकासार्थ विद्यार्थी (SFD), थिंक इंडिया जैसे कई अन्य विषय विशेष चर्चा में रहे। बैठक का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने संयुक्त रूप से किया।

गीता और गांधी के पुनर्स्मरण से विश्व

उद्घाटन सत्र मे मंचासीन अतिथि बायें से डॉ. प्रवीण गर्ग, श्री उमेश दत्त, प्रा. मिलिन्द म

नयी दिल्ली। "भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत" के विषय पर केन्द्रित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'वंदेमातरम्', 'भारत माता की जय' के साथ 'भ्रष्टाचारियों सावधान, जाग उठा है नौजवान' के उद्घोष के बीच ध्वजारोहण के साथ सम्पन्न हुआ। तीन दिवसीय इस अधिवेशन का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी ने किया।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री लाहोटी ने कहा कि आजादी के 65 वर्षों बाद भी संविधान में प्रदत्त न्याय, समता, स्वतंत्रता और अधिकार आम आदमियों को उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। भारत में रामराज्य की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकेगी जब प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय समान रूप से मिलेगा। यह गीता और गांधी के विचारों की पुर्नस्थापना से ही सम्भव है।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की वर्तमान चुनौतियों व समस्याओं के लिए राजनैतिक महत्वाकांक्षा व अनीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने

गुरू बनेगा भारत : न्यायमूर्ति लाहोटी

ठे, श्री आर सी लाहोटी, श्री विजय कपूर, सुश्री मनन चतुर्वेदी, श्री भारत भूषण मंच

इसके समाधान के लिए संस्कार, संस्कृति व संस्कृत की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति के साथ जब महत्वाकांक्षा व व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ जाता है तो राजनीति गंदी हो जाती है। इसके सुधार के लिए युवाओं को आगे आना होगा। ऐसे में विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली विद्यार्थी परिषद की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में जब–जब चुनौतियां आयी हैं, तब–तब विद्यार्थी परिषद ने हताश व निराश समाज में नई ऊर्जा का संचार किया है। बात चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की हो या भ्रष्टाचार की, सभी समस्याओं से लड़ने हेतु परिषद के कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक सदैव तत्पर रहे हैं। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि वह अपनी ऊर्जा व शक्ति को राष्ट्रहित में लगाएं। श्री मराठे ने कहा, 'छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति दोगुनी हो जाती है। एक विद्यार्थी

के नाते और दूसरा नागरिक के नाते। समाज में परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब व्यक्तिगत जीवन में सकरात्मक परिवर्तन हो। व्यक्ति निर्माण इसका माध्यम है और परिषद पिछले 63 वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रही है।'

श्री मराठे ने संस्कारित, संगठित व राष्ट्र भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के बल पर परिषद द्वारा हर समस्या के समाधान करने के संकल्प को दोहराया। श्री मराठे ने कहा कि भ्रष्टाचार से सामान्य जनता त्रस्त है। वर्तमान केन्द्र सरकार अपनी सारी नैतिक मर्यादा छोड़कर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार के नए खुलासों से यह साबित हो चुका है कि सरकार के कई मंत्री देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भ्रष्ट केन्द्र सरकार की नीतियों व उसके द्वारा अंजाम दिए गए घोटाले और कालेधन को वापस लाने हेतु निरंतर संघर्ष कर रही है। छात्र–युवा शक्ति के बल पर परिषद् ने सड़क से लेकर संसद तक धरने व आन्दोलन के जरिए देश की जनता को आगाह करने का काम किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ने देश के छात्र–युवाओं को आहत किया है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सड़को पर उतरकर इसके विरूद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। अभाविप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए सड़क पर उतर चुकी है और इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन के माध्यम से अभाविप सरकार से मांग करती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर सजा का प्रावधान हो। साथ ही देश की व्यवस्था में सुधार कर तंत्र को प्रभावी एवं मजबूत बनाया जाए।

विशेष भाषण सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लोकपाल की बहस से आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ लोकपाल बन जाने मात्र से ही भ्रष्टाचार के समूल को नाश होना असंभव है। श्री आंबेकर ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राइट टू रिकाल व राइट टू रिजेक्ट की मांग अव्यावहारिक है। इसकी जगह हमें व्यापक चुनावी सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक चुनावी व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर नहीं आएंगे और चुनावी भ्रष्टाचार की समस्या से निजात नहीं मिलेगी।

श्री आंबेकर ने कहा, 'देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है साथ ही इसे दिग्भ्रमित करने की साजिश भी चल रही है। देश को इन साजिशों की प्रकृति को समझने की जरुरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष या टीम का आंदोलन नहीं है बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे प्रयासों में भेद–भाव की नीति अपनाने की जगह सामूहिक रूप से संघर्ष करने की आवश्यकता है।'

विदेशों में जमा काले धन को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार नीतिगत घोटाले कर रही है, इसलिए अभाविप ने तय किया है कि हम भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कानून, व्यवस्था व सरकार में परिवर्तन लाने के लिए रणनीति तय करेंगे।

अभाविप के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री व यूथ अगेंस्ट करप्शन के संयोजक सुनील बंसल ने कहा, 'भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ने देश के छात्र–युवाओं को आहत किया है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसके विरुद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। अभाविप का यह भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन केवल विरोध के लिए नहीं है

बल्कि समाधान तक पहुंचाने के लिए है। अभाविप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए सड़क पर उतर चुकी है और इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी।'

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की जनता में आक्रोश है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार इसके खिलाफ लड़ने का ढोंग कर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। 'यूथ अगेस्ट करप्शन' के माध्यम से अभाविप के नेतृत्व में युवा इस भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेकने के लिये सड़कों पर उतर चुके हैं। श्री बंसल ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम को आक्रामक रणनीति के साथ चलाने की घोषणा करते हुए सीधी कारवाई के माध्यम से प्रभावी और मजबूत आंदोलन खड़ा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में युवाओं के मिले अपार जनसमर्थन ने समाज में यह अवधारणा बदली है कि देश में युवा, विद्यार्थी केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए आंदोलन चलाता है। आज का युवा देश व समाज की समस्याओं के लिए फैशन और फेसबुक से ऊपर उठकर सड़कों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है।

श्री बंसल ने कहा कि अगर विकसित भारत का निर्माण करना है तो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें कुछ पन्ने हमारे नाम नहीं होंगे बल्कि पूरा इतिहास हमारे नाम होगा।

अधिवेशन में भ्रष्टाचार विषय को लेकर आयोजित प्रदर्शनी में यूथ अगेंस्ट करप्शन द्वारा देशभर में चलाए गए रचनात्मक एवं आंदोलनात्मक गतिविधियों की चित्र–प्रदर्शनी के साथ–साथ पेंटिंग एवं कार्टून लगाए गये। प्रदर्शनी के माध्यम से देशभर के युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लडने और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका तय करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्र नीरज ने कैनवास पर भ्रष्टाचार की खामियों को बखूबी उतारा है। राजनेताओं की लोकतंत्र में लूट, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, अन्ना आंदोलन के दौरान हथकड़ी लगा लोकतंत्र और न्याय के तराजू में रुपयों के बल पर भ्रष्टतंत्र का शिकार होता आम आदमी इस प्रदर्शनी के खास चित्र रहे। लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा प्रियंका छाबड़ा, अंतिमा तोमर और ज्योति देसवाल के अलावा खालसा कॉलेज की साध्वी सिंदुरा ने भी इंटरनेट और समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ फुटेज और कतरनों से तैयार क्लिप आर्ट की प्रदर्शनी लगाई । प्रदर्शनी को अधिवेशन में आये प्रतिनिधियो ने काफी सराहा।

अधिवेशन के दौरान विशेष रूप से रा0स0सं0 के सह सर–कार्यवाह श्री सुरेश सोनी एवं श्री दत्तात्रेय होसबले, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भाटिया,पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री गीता ताई, पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अतुल भाई कोठारी एवं राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री बी0एम0एस0 बी. सुरेन्द्रन, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री महेन्द्र कुमार, सुरेश भट्ट, पूर्व उपराज्यपाल विजय कपूर, सांसद प्रकाश जावडेकर, दी0द0 शोध संस्थान के श्री अभय महाजन आदि विविध राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

वर्ष 2011 का प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार

श्रीमती मनन चतुर्वेदी को जयपुर, राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मनन चतुर्वेदी को अनाथ एवम् निराश्रित बच्चों का, अनूठे रुप से मातृत्व अंगीकार करते हुए उनके पुनर्वसन हेतु किये कार्य के लिए 'प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2011 सेसम्मानित किया गया। श्रीमती मनन चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार दिल्ली में 4 जनवरी कोहुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 57वें राष्ट्रीय अधिवेशन मे एक विशेष समारोह मेंश्री आर.सी. लाहोटी (भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय) द्वारा प्रदान किया गया।

श्रीमती मनन चतुर्वेदी जी को 'फैशन डिजाईनिंग' का अध्ययन करते समय ही एक अमरीकी वस्त्र बनाने वाली कंपनी ने उनका चयन किया था। उस कंपनी को हां या ना जबाब देने के लिए माता–पिता के साथ बात करने के लिए जब मनन जी जयपुर लौट रही थी तब सिंधी कैम्प बस अड्डे पर उन्होंने एक हृदय–विदारक दृश्य देखा। एक 11–12 साल की लड़की जिसके तन पर ढकने के लिए वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं था, कचरे के ढेर में खाने के लिए तलाश कर रही थी। उसी क्षण उनके मन में सवाल खड़ा हुआ की मेरे अपने देश मे लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नही हैं, तो विदेशी लोगों के लिए वस्त्र बनाने के लिए मैं विदेश क्यो जाऊँ? वही क्षण था जिसके कारण उन्होंने अमरीकी वस्त्र कंपनी के लिए विदेश जाने का विचार त्याग दिया और समाज में वंचित रह गये बच्चों और उन तब को केलिए सेवाकार्य शुरु किया। जो सुरमन पालना सुख आश्राम के रुप में दिख रहा है।

वह शुरुवात में कच्ची बस्तीओ में बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांटना व दवाईयाँ उपलब्ध कराना जैसे कार्य करती थी, लेकिन मनन जी को निराश्रित बच्चों की बेबसी परेशान करती थ। इसी दौर में मरणोन्मुख सवा साल की गौरी मनन जी के 'पालना' की पहली सदस्य बनी। काबिल डॉक्टरों के सहयोग और मनन जी के समर्पण से गौरी को जीवनदान मिला। अब वो स्वस्थ हैऔर स्कूल मेंपढ़रही है। मनन चतुर्वेदी जी ने एक हजार स्क्वेयर फूट वाले एक प्लॉट में 17 बच्चों के साथ पालना की शुरुआत की अब कुल 44 बच्चों से ज्यादा बच्चे मनन जी के इस विशाल परिवार मेंरहते हैं। इन बच्चों में मनन जी के अपने तीन बच्चे भी हैं। मनन जी सिर्फ अपने तीन बच्चों की ही नहीं बल्कि सभी 44 बच्चों की मां हैं। ऐसे देखा जाये तो मनन चतुर्वेदी अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए अनाथ आश्रम चलाती है, लेकिन असल में यह अनाथ आश्रम नहीं अपितु पूरा परिवार है। इसलिए मनन जी ने अपने इस कार्य के बारे में दो प्रण भी रखे हैं। पहला सरकार से मदद नहीं लेनी और दूसरा पालना में आये बच्चों को किसी और की गोद में नहीं देना। उनका कहना है की क्या कोई अपना घर चलाने के लिए सरकारी मदद लेता है और क्या कोई मां अपने बच्चों को किसी और को गोद देती है?

शभुकामना कार्ड छपाना, हस्त व्यवसाय से बनाई गयी वस्तु की बिक्री, बोगन वेलीया नामक मासिक का प्रकाशन, चित्र बनाना ऐसे कई छोटे–छोटे उपक्रमों से आने वाले आय से पालना का खर्चा चल रहा है। मनन जी के इस कार्य में कई दान दाताओं ने भी अपनी–अपनी हैसियत से अपने हाथ बटाये हैं। मनन 'सुरमन संस्थान' नामक संगठन के माध्यम से पालना के साथ ही परित्यक्त महिलाओं के लिए 'कोशिश' नाम से एक उपक्रम चलाती हैं एवं 'फुलवारी' प्रकल्प के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियो में रहने वाले बच्चों के लिए पाठशाला चलाती हैं। अब मनन जी सुरमन ग्राम के निर्माण की ओर बढ़ रही हैं। वो एक ऐसा गाँव बनाना चाहती हैं जहां ये सभी बच्चे स्वाभिमान की जिंदगी जी सके और जहां ना केवल ये अनाथ और निराश्रित बच्चेअपितु परित्यक्त महिलाये एवं बेघर वृद्ध खुली हवा में सांस लेसके।

विदित हो कि प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार का प्रारंभ 1991 मेंइस श्रेष्ठ प्रेरणादायी व्यक्ति की पावन स्मृती मेंहुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी निधि न्यास का यह संयुक्त उपकम है। विभिन्न समाजपयोगी विषयों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु समाज के सम्मुख लाना और ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति समुचे युवा वर्ग की कृतज्ञता प्रकट करना यह इस युवा पुरस्कार का प्रायोजन है। इस पुरस्कार में नगद राशि रु. 50000/–, प्रमाणपत्र एवं स्मृतिचिन्ह समाविष्ट है।

स्वप्नभंग से भ्रम टूटा, नये तरीकों की खोज जरूरी

सुनील आंबेकर

मै कानपुर से मुगलसराय रेलयात्रा में था। देर रात में ट्रेन पकड़ पाया था, इस कारण सुबह थोड़ी देरी से नींद खुली, तो काफी आवाज हो रही थी। एक कॉलेज का लड़का दूसरे से पूछ रहा था, यार ये 'वॉल स्ट्रीट' क्या है? जबाब आया पता नही, कोई वॉल नाम का अंग्रेज होगा। लेकिन यह तो अमेरिका है। यार, वहाँ तो पुराने अधिकतम अंग्रेज ही तो है। यह बाते चलते–चलते गंभीर हो गयी कि अमेरिका में भी लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जैसी बाते तो हमारे जैसे गरीबों के देश में होती हैं। और अमेरिका तो दुनिया भर मे इसी पर राजनीति करता है। और चर्चा राजनीति पर घूम गयी। दिन प्रारंभ हो गया, स्टेशन भी आ गया। मैं भी भूल गया।

फिर दिल्ली–पटना विमान से गया, तो हमारा स्थानीय कार्यकर्ता लेने आया था। उसने कहा किंग फिशर सहित सारे विमान रद्द हैं, आप का यह एक ही विमान आया है। पता नहीं क्या घाटा लग गया है इन कंपनियो को? उसने कहा की वह दोपहर थोड़ा व्यस्त रहेगा क्यों की उसकी चचेरी बहन अमेरिका से आ रही है। मैंने थोड़ा और पूछा उसने कहा, अमेरिका से है, यह बताने के लिए दीदी ने मना किया है। मैनें कहा, अब तो बिहार में कानून–व्यवस्था ठीक है, बताने में क्या हर्ज है? वैसे तो लोग अपनी शान में बिना पूछे ही बता देते है। उसने आगे कहा, नहीं, नहीं यह बात नहीं है। दीदी ने कहा टैक्सी वालों को मत बताना। वह जब मुंबई विमान तल पर टैक्सी पकड़ रही थी, और टैक्सी वालों को जब पता चला कि वह अमेरिका से है, तो वह चर्चा करने लगे कि यार यह सब भिखमंगे है, अब अमेरिका में नौकरियाँ जा रही है, तो यह लोग भिखमंगो की तरह भारत लौट कर आ रहे हैं। वैसे दीदी का काम तो ठीक ही चल रहा है वह किसी कार्यक्रम हेतु यहाँ आयी है। उसे यह डर था कि कही पटना के टैक्सी ड्राइवर भी इसी तरह सोचकर व्यंग करेंगे, तो बड़ा बूरा लगेगा। पहले तो मझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारे मुंबई टैक्सी ड्राईवर भी अमेरिका सहित दुनियाभर की आर्थिक गतिविधियों का गहरा ज्ञान रखते है। लेकिन उनका यह ज्ञान उनके विमान तल पर रोज अमेरिका से आ रहे यात्रियों की बातों से ही बढ़ रहा था, जों बिल्कुल जमीनी अनुभवों पर आधरित था।

आजकल भारत में खुदरा/किराया (Retail) व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की चर्चा जोरों पर है। पूरी संसद एक सप्ताह से ठप्प थी। सरकार ऐसे निवेश को लाने पर उतारू है, तो पूरे देश में लोग विरोध में आंदोलन कर रहे। विपक्ष ने विरोध का जोरदार मोर्चा संभाल रखा है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने 2004 में जहाँ इसकी वकालत की थी, उसने भी दुनियाभर के अनुभवों के आधर पर 2009 के अपने घोषणा पत्र में इसको नकार दिया था व अब पुरी तरह विरोध का झंडा थामे चल रहा है। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट मतलब, वहाँ का शेयर मार्केट मुख्यालय है, जहाँ की सूचीबद्ध (Listed) कंपनियो का दुनियाँ के कई देशों से अधिक बजट है, वे पूरी दुनियाँ के अधिकतम व्यापार को चलाती

है। पूरा अमेरिका गुणवत्ता के नाम पर इन्हीं कंपनियो की ब्रांण्डेड वस्तुएँ खरीदने में लगा रहता है। लेकिन आज इन्हीं कुछ लगभग 500 कंपनियों के हाथ में अमेरिका की आर्थिक नाड़ियाँ हैं व सारी अमेरिकी नीतियाँ इनके हित में चलायी जाती हैं। परिणाम स्वरूप इनका झूठ व अपयश लगातार छिपता रहा। लेकिन अब रोजगार घटने लगे, सामाजिक क्षेत्र का खर्च घटने लगा तथा कंपनियाँ/बैंक डूबने लगे तो सारा भेद खुलता जा रहा है। और जिस वॉल स्ट्रीट को आधुनिक समय में नया भगवान माना जा रहा था, उसी के खिलाफ अमेरिका में 'वॉल स्ट्रीट को कब्जा करो' (Occupy Wall Street) आंदोलन प्रारंम्भ हो गया। कुछ कंपनियाँ व सरकार मिलकर तैयार एकाधिकार पर आधरित विकास की यात्राा का यह दुखद अध्याय है। यह अंत इसलिए नहीं है क्योंकी पुरी दुनिया के चीन सहित कई देशों के व्यापारिक हित इन कंपनियों से जुड़े है, इसलिए इनके साम्राज्य को बचाकर रखने का प्रयास केवल अमेरिकी सरकार नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश कर रहे हैं। यूरोप के लगभग सभी देशों में भी इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तथा वहाँ भी आंदोलनों का स्वरूप काफी व्यापक है सारी सरकारे उससे भयभीत है।

हमारे देश में भी दलाल स्ट्रीट है व उसे पूरी तरह आर्थिक केंद्र बनाने के नीतिगत प्रयास में यह प्रस्तावित निवेश बड़ी भूमिका निभायेगा। भारत में अभी भी बहुत कुछ व्यापार इन सूचीबद्ध कंपनियो से बाहर है तथा छोट–मोटे उत्पादक व खुदरा व्यापारी हमारी आर्थिक गतिविधि का बहुत बड़ा हिस्सा है।

यह सभी मानेंगे, कि वर्तमान व्यापार में सुधार की जरूरत है ताकि मुनाफाखोरी कम हो, गुणवत्ता बनी रहे तथा किसानों या छोटे–छोटे उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल पाये, व रोजगार अधिक से अधिक मिले। लेकिन क्या इन सुधारों को विदेशी निवेश के अभाव ने रोका था या सरकार की अनदेखी तथा सूचीवद्धे कंपनियों के नीतिगत विषयों पर दबाव ने रोका है। सरकार कह रही है कि नये रोजगार प्राप्त होंगे लेकिन कौन से रोजगार? दुकान में काम करने वाले रोजगार? अर्थात, स्वरोजगार कितने बंद होंगे इस पर चुप्पी है। और स्वरोजगार से नौकरी (Self Employment To Wage Employment) और वह भी असंगठित क्षेत्र में कहते है यह बाजारवाद (Market Economy) मतलब मुक्त व्यापार है, आधुनिकता है जैसे कोई यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हो, ऐसा प्रचारित किया जाता है। लेकिन यह व्यवस्था कंपनियों को मुक्तता व शेष लोगों को उनके भरोसे पर रहने के लिए मजबूर कर देती है।

आज इन्हीं के भरोसे आराम से रह पाने का स्वप्न ज्यों अमेरिकी युवाओं को दिखाया गया था, काफी वर्ष वह चल भी पाया है, दुनिया भर के शोषण से उस स्वप्न को दुनिया भर के युवाओं ने भी देखा। आज अमेरिका व्यवस्थाओं की उजागर हो रही आंतरिक कमियों से उत्पन्न संकट से इन सभी का स्वप्नभंग हुआ है।

लेकिन निराशा को त्यागने की जरूरत है। अमेरिका भी तत्काल डूबने वाला नहीं है। भारत भी कमजोर नहीं है। बहुत बातें सकारात्मक भी हैं। भारत के युवाओं की प्रतिभा व परिश्रम उभरकर आ रहे है। जरूरत है अपनी नीतियों को पुनर्गठित करने की। हमारा सब कुछ अच्छा भी नहीं है तथा दुनियाभर का पूरा गलत भी नहीं।

हर पीढ़ी को, हर देश को स्वयं चिंतन करना होता है, मूलभूत सिद्धांतो एवं अपने अभी तक के अनुभवों का। यह पीढ़ी तो, पिछले दो शताब्दियों में हुए आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं के प्रयोगों के अनुभवों से अधिक परिपक्व हुई है तथा नई तकनीकी भी अब साथ में खड़ी है। इसलिए मार्ग ज्यादा कठिन नहीं, जरूरत है, स्वप्नभंग की निराशा को छोड़कर, नये तरीके–नये उत्साह से ढूंढने की।

(लेखक अ.भा.वि.प. के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं।)

महामंत्री प्रतिवेदन वर्ष: 2010-2011

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राजधानी व ऐतिहासिक महानगरी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में आयोजित हो रहे अभाविप के 57वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने–कोने से आए आत्मीय कार्यकर्ताओं, विचार परिवार के बन्धुओं, मीडिया तथा वरिष्ठ अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है। अभाविप विगत् वर्षो से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत है। आज इस अवसर पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आन्दोलन को और प्रखर बनाने के संकल्प को दोहराते हैं।

देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इस वर्ष भी देश का युवा सड़क से संसद तक संघर्षरत है। यह अधिवेशन युवाओं की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाकर वर्तमान में चल रहे आन्दोलन को और भी प्रखर व मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

छात्र, आंदोलनों में, छात्र संघ चुनावों व छात्र संघों की भूमिका को स्थापित करने में भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की ऐतिहासिक भूमिका रही है। हमेशा वामपंथी विचार का गढ़ कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रवाद का झण्डा बुलन्द करने का काम दिल्ली के छात्रों ने किया है।

विगत वर्ष 2010 में बैंगलोर में आयोजित अधिवेशन में देशभर से 8,500 कार्यकर्ता जुटे थे और इसमें हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बनाने व भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो रहे सभी आंदोलनों में अपना पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया था। हमने तय किया था कि 6 जनवरी 2011 से देशभर में भ्रष्टाचार के विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। 6 जनवरी को 500 से भी अधिक स्थानों पर प्रदर्शन कर हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुवात की। 30 नवम्बर 1 एवं 2 दिसम्बर को ऐतिहासिक 72 घण्टे के महापड़ाव तक कई चरणों में भ्रष्टाचार व कालेधन के विरुद्ध यह आंदोलन जारी रहा। 27 जनवरी को देश के लगभग 450 स्थानों पर प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों युवाओं की सहभागिता रही। 17–18 फरवरी को देश के 24 प्रदेश मुख्यालयों पर 24 घण्टे का मौन उपवास किया गया, जिसमे 5,000 से अधिक छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। बाबा रामदेव पर बर्बर पुलिस दमन के विरोध में भी पूरे देश में 400 से अधिक स्थानों पर परिषद् के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। श्री अन्ना हजारें के समर्थन में भी सैकड़ों स्थानों पर परिषद् के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए।

जन्तर–मन्तर पर 4 मार्च को 5,000 छात्रों का प्रदर्शन हो या लखनऊ प्रदर्शन में बर्बर लाठीचार्ज या देहरादून, बैंगलूर, गुवाहाटी सहित कई प्रदेशों के मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शनों से इस आन्दोलन को और गति देने का काम हम सब ने किया। देश में चल रहे विभिन्न आंदोलनों में समय–समय पर हमने अपना योगदान दिया है।

यह आन्दोलन प्रथम चरण में केवल विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों तक ही सीमित था लेकिन समाज के प्रभावशाली युवाओं तथा गणमान्य नागरिकों के समर्थन एवं सुझावों से यह आन्दोलन देश के युवाओं तथा जनता तक पहुंचाया जा सके, भ्रष्टाचार के समग्र उन्मूलन के लिए कोई ठोस सुझाव भी सरकार को दिये जाएं एवं लोकपाल के साथ–साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाय ऐसा विचारकर 12 मई 2011 को दिल्ली में (YAC) Youth Against Corruption मंच का गठन किया गया। इसका नेतृत्व श्री सुनील बंसल जी को सौंपा गया, कई बुद्धिजीवियों एवं समाज में प्रतिष्ठित युवाओं ने इसका समर्थन किया व इसका हिस्सा बन प्रत्यक्ष आन्दोलन में कुदने का निर्णय

लिया। मंच के गठन के दौरान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात समाजसेवी श्री अशोक भगत (रांची), श्री अलफासों (पूर्व प्रशासनिक अधिकारी) एवं श्री आर. बाल सुब्रमण्यम (बैंगलुरू) संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। वर्तमान में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन का नेतृत्व YAC के माध्यम से चल रहा है, जिसको देशभर में कई युवक/सामाजिक/धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। देशभर से प्राप्त समर्थन–पत्रों के अनुसार 300 से भी अधिक संगठनों ने YAC का समर्थन किया है।

YAC एवं ABVP ने न केवल धरने, प्रदर्शन एवं उपवास किये बल्कि युवाओं की ओर से आये समाधान/सुझाव पर चर्चा करते हुए 14 सूत्रीय सुझाव–पत्र तैयार किया गया। भ्रष्टाचार के विरूद्ध ठोस कानून बने व विदेशों में कालेधन को भारत वापिस लाने के मुद्दे को प्रखरता से उठाया गया। समग्र व्यवस्था परिवर्तन के विभिन्न मुद्दो, जिसमें व्यापक चुनाव सुधार, पुलिस कानूनों में सुधार, न्यायिक व्यवस्था परिवर्तन में सुधार, प्रशासनिक सुधारों एवं व्यापक शैक्षणिक सुधारों हेतु देश के पांच प्रमुख केन्द्रों दिल्ली, मुम्बई, भोपाल, हैदराबाद व बैंगलूरू में इन सुधार के विशय विशेषज्ञों की सहायता से प्रारूप (Draft) तैयार करने का काम भी YAC के माध्यम से शुरू किया गया है। कालेधन को सरकार कैसे वापिस लाए, इस हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दिये गए। निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठन (NGO) को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाने हेतु स्वतन्त्र कानून बनाये जाये इस मांग को उठाते हुँए समाधान प्रस्तुत करने वाला एक विचारार्थ बिल (Prevention of Bribery in Private Sectors / NGO Sector Bill 2011) सरकार तथा देशभर के बुद्धिजीवियों में चर्चा हेतु भेजा गया।

सबसे महत्त्वपूर्ण देश में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार UPA – 2 को सत्ता से हटाने की मांग व आम जनमानस का जागरण करने का व्यापक प्रयास किया गया। YAC के नेतृत्व में देशभर के 454 जिलों में जिला रैलियों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक छात्र व युवा सड़कों पर आएं। 9 अगस्त 2011 को देशभर में भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलते हुए व्यापक चक्का जाम किया गया। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी हुई। 18 अगस्त अखिल भारतीय कॉलेज बंद के आहान पर देशभर के 365 जिलों में, 1804 स्थानों पर 16375 कालेज व शैक्षणिक संस्थान बन्द कर छात्रों ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष का समर्थन किया।

9 अगस्त 2011 को देश भर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को मानव श्रृंखलाओं के माध्यम से उठाया गया। देश के 331 जिलों के 785 स्थानों पर 795 मानव श्रृंखलाओं में छात्र, युवा जुटे। इन मानव श्रृंखलाओं में 417, 363 छात्रों, युवाओं ने भाग लिया, देश के कोने – कोने में प्रभावी आन्दोलन किया गया, बैंगलुरू में 25 हजार छात्रों द्वारा मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रही, सिलचर व गोहाटी में भी युवाओं व छात्रों ने प्रदर्शन कर मुद्दे का समर्थन किया। 18 अक्टूबर 2011 के प्रदर्शन में भी देशभर में 410

स्थानों पर हजारों युवाओं ने अपना योगदान दिया। जिला सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परिसंवादों के माध्यम से भी इस मुद्दे को जनमानस का मुद्दा बनाने में YAC व ABVP ने लगातार वर्षभर प्रयास किये। 30 नवम्बर, 1, 2 दिसम्बर को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर 72 घंटे का महापड़ाव हुआ, छात्र, युवा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लगातार धरने पर डटे रहें। 50 हजार से अधिक छात्र, युवा व समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव इस महापड़ाव का हिस्सा बने। 200 यात्राओं के माध्यम से युवाओं व जनता के बीच YAC का जाना हुआ। 25 लाख छात्रों से परिसर में सम्पर्क तथा अन्य हर तबके के लाखों लोगों से सम्पर्क करते हुएं व्यापक प्रचार प्रसार कर इस मुद्दे को और प्रखरता से उठाने का प्रयास YAC ने किया। भ्रष्ट कुल. पतियों की सूची 12 मई 2011 को जारी करने के तुरन्त बाद प्रत्यक्ष ऐसे भ्रष्ट कुलपतियों के खिलाफ व्यापक आन्दोलन किया गया। प्रसन्नता की बात यह है कि कर्नाटक सहित कई प्रदेशों में आन्दोलन के कारण कई कुलपतियों को उनके पदों से हटाया गया।

देशभर में स्थानीय इकाई स्तर पर भी शिक्षा के कई मुददों के हल हेतु हमने संघर्ष किया है। स्थानीय स्तर पर SC/ST छात्रों की मांगो को लेकर संघर्ष हुआ है। कई प्रदेश सरकारों को अपने आन्दोलन व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छात्रावासों की दशा में सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। प्रत्यक्ष परिसर व न्यायालय में अपना यह संघर्ष सतत जारी है।

शैक्षणिक आन्दोलनों के साथ–साथ सामाजिक चेतना व सामाजिक महत्त्व के विषयों पर आन्दोलनों को गति देने तथा संदेशात्मक आन्दोलन भी परिषद् ने इस वर्ष किये है। जैसे महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाला दिल्ली का राधिका हत्याकांड के विरोध में दिल्ली वि.वि. का आन्दोलन हो, राष्ट्रद्रोही बयान देने व राष्ट्रदोही गतिविधियों में लगे सैय्यद गिलानी, अरूणधती राय, विनायक सेन आदि का व्यापक विरोध। भारतीय छात्र व युवाओं की भावना को प्रकट करने का काम विद्यार्थी परिषद् ने किया है।

2011 में जिन प्रदेशों में छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न हुए है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सबसे बड़ा व प्रभावशाली संगठन उभर कर आया है। इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय में परिषद् का झण्डा दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने बुलन्द किया है तो मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात के एम.एस. वि.वि.बडोदरा, हिमांचल प्रदेश में विरोधियों के मुकाबले एक तरफा जीत अ.भा.वि.प. की हुई है। मध्यप्रदेश के 8 वि.वि. के छात्रसंघों के अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज का इतिहास रचने का काम किया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में ठम्ए उड़ीसा, असम, प.बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी महत्त्वपूर्ण सीटें जीत कर परिषद् ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

SEIL अंर्तराज्य छात्रजीवन दर्शन के तत्वाधान में पूर्वोतर के सात राज्यों के छात्रों हेतु भारत भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो समूहों में यह छात्र 1 जनवरी से 17 जनवरी तक देश के 10 राज्यों में भ्रमण हेतु गए। अपने भ्रमण के दौरान देश के कई गणमान्य महानुभावों से इन छात्रों का प्रत्यक्ष मिलना हुआ। कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजनैतिक नेताओं सहित कई बुद्धिजीवी, समाज सेवियों से मिलना हुआ। इस यात्रा के दौरान दस प्रदेशों के 15 शहरों और 20 विश्वविद्यालयों में छात्रों का जाना हुआ तथा 138 परिवारों में **SEIL** प्रतिनिधि रहे।

अपने देश की संस्कृति, परम्पराओं, मान्यताओं का दर्शन विदेशी छात्रों को हो जीवन प्रयन्त भारत के प्रति विश्वास व सम्मान, प्रेम, सम्पर्क रहे ऐसा प्रयास **WOSY** के तत्वधान में किया जाता है। इस वर्ष चण्डीगढ में 19, 20 फरवरी को सास्कृतिक विविधता –एक सुखद अनुभूती (Celebrating Cultural Diversity) नाम से अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित हुआ। परिसंवाद में 38 देशों के 230 छात्र–छात्राए इसमें सहभागी रहे।

देश के उन प्रतिभावान छात्रों में भी हम आज प्रभावी उपस्थिति में आ गए है जो देश के चुनिंदा शिक्षण संस्थानों (IIT, IIM & NIT) में शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में भागीदार बनते है। इस वर्ष पुणे मे थिंक इंडिया (THINK INDIA) कार्यशाला का आयोजन हुआ। 20 शैक्षिणक संस्थानों के 56 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में सहभागी बने। छात्रों का रूझान सेवाकार्य की और हो छात्र प्रत्यक्ष देश के विकास व सेवा कार्य मे सहभागी बने इस हेतु SFD के तत्वाधान मे कई सराहनीय कार्यक्रम चलाए गए। मध्य प्रदेश मे जल संरक्षण निमित बूंद यात्रा, हरियाणा में जल एवं पक्षी संरक्षण हेतु जल पात्र स्थापित करना, उत्तरांचल में व्यापक वृक्षारोपण, गुजरात में मिट्टी के बर्तनो (पक्षियों को जल हेतू) को पुनः प्रचलित करने हेतु 10,000 वर्तन वितरण, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के रक्तदान, आदि का आयोजन कर छात्रों मे सेवा दृष्टि जागृत करने का प्रयास किया गया ।

अभाविप के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़, झारखंड तथा विशेष रुप से दंतेवाड़ा व अन्य घटनाओं के होने के बाद तुरंत उनके विरोध में सड़कों पर आकर नक. सलवाद के विरोध व देशवासियों व सुरक्षाकर्मियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। विनायक सेन मामले में भी विदेशी पर्वेक्षक मण्डल एवं अन्य नक्सल समर्थकों का विरोध कर नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष खड़ा करने का प्रयास परिषद् ने किया है। पुणे (महाराष्ट्र) में परिषद् के विरोध के चलते नकसल समर्थक डॉ. विनायक सेन के होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने पड़े ।अभी तक प्राप्त आकड़ों के अनुसार अपनी सदस्यता 13, 70, 044 हुई है। अनेक नए स्थानों पर भी विद्यार्थी परिषद् का विस्तार हुआ है। लेह से कन्याकुमारी, अंदमान निकोबार तक के साथ–साथ परिषद का कार्य 3,655 स्थानों पर पहुँचा है, 4040 महाविद्यालयों में अपनी सक्रिय इकाईयां खड़ी हुई हैं। इस वर्श वार्षिक अधिवेशनों, इकाई स्तर से प्रदेश व अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के वैचारिक प्रबोधन हेतु अभ्यास वर्गों की लम्बी श्रृखला खड़ी हुई है।

संगठनात्मक विस्तार के साथ–साथ कार्यक्रमों में भी निरन्तर वृद्धि जारी है। 12 जनवरी 2011 विवेकानन्द जयन्ती (युवा दिवस) के कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर 1, 260 स्थानों पर 2, 176 कार्यक्रम हुए। 9 जुलाई (स्थापना दिवस) राश्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के कार्यक्रम 1, 110 स्थानों पर 1, 727 हुए है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर पुण्य तिथि समाजिक समता दिवस के कार्यक्रम 555 स्थानों पर 671 की संख्या में हुये।

नियमित प्रकाशन के माध्यम से भी अभाविप कई कार्यकमों मुद्दों को कार्यकर्ताओं व समाज तक पहुंचाते हैं। अपनी मासिक पत्रिका राश्ट्रीय छात्र शक्ति का नियमित प्रकाशन हुआ है। कई प्रदेशों से मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं का सफल प्रकाशन हो रहा है। सांदीपनी, छात्र उद्घोष, छात्रशंखनाद मानव शक्ति आदि का सफल प्रकाशन निरन्तर जारी है। इस वर्ष कार्यकर्ताओं द्वारा किये प्रत्यक्ष सर्वे के आधार पर शिक्षा के व्यापारीकरण के कई पक्षों को उजागर करते हुए रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है। विभाग संगठन मंत्री वर्ग की भाषण माला पुस्तक प्रबोधन एवं 'भविष्य के भारत की कल्पना' पुस्तक का प्रकाशन भी केंद्रीय कार्यालय की ओर से हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 'हल्ला बोल सत्ता छोड़ों, YAC बुलिटिन का भी प्रकाशन हुआ है। केंद्रीय सचिवालय मुंबई, जनसंपर्क कार्यालय दिल्ली, राष्ट्रीय छात्रशक्ति का नियमित प्रकाशन, अन्य नियमित प्रकाशन तथा e-ABVP के सुचारु संचालन से हमारी कार्यकुशलता व प्रभाव में भी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्ताव

प्रस्ताव क्रं. 1

देश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य

देश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य अत्यन्त चिन्ता. जनक है, जहाँ एक ओर उच्च शिक्षा संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता ने सामान्य जनमानस को निराश किया है वहीं दूसरी ओर महंगी होती शिक्षा ने देश के गरीब, मेधावी छात्रों को शिक्षा से वंचित होने को मजबूर कर दिया है। सत्ता में आने के मात्र 100 दिनों के भीतर शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का दम भरने वाले मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार के भ्रष्ट कारनामों को ढकने मे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा किये वायदों की फाईलें धूल फांक रही हैं। ज्ञान आयोग और यशपाल कमेटी की सिफारिशों का उत्साह अब ठण्डा पड़ने लगा है। शिक्षा सुधार सम्बंधी अनेक बिल संसद के पटल पर आने के साथ ही मूर्छाग्रस्त हो जाते हैं। शिक्षा में व्यापारीकरण की गति लगातार तीव्रतर होती दिखाई देती है। अभाविप का यह 57 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मानव संसाधन विकास मंत्री की शिक्षा के प्रति उदासीनता व्यापारीकरण को पुष्ट करने वाली योजनाओं, नीतियों एवम् गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निन्दा करती है।

अभाविप द्वारा हाल ही में प्रकाशित शुल्क संरचना सर्वे रिपोर्ट से देश की उच्च शिक्षा, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा में भारी विसंगतियों व घोर व्यापारीकरण से पर्दा उठाता है। देश के विभिन्न राज्यों मे किस तरह शुल्क संरचना में भी अन्तर व वि. संगतियाँ एवं महाविद्यालयों की उपलब्धता में भी विभिन्न राज्यों में भारी अन्तर है, जनजातीय व पिछडे क्षेत्रों में यह अनुपात और भी डरावना एवम् अव्यावहा. रिक है। यही दशा मेडिकल, फार्मेसी, कृषि आदि विषयों मे महाविद्यालयों की देशभर में दिखाई देती है अभाविप द्वारा किया यह जमीनी सर्वे देश की उच्च शिक्षा के असली चित्र को उजागर करता है तथा मानव संसाधन विकास मंत्री के दावों की पोल खोलता है। समान शुल्क संरचना, व्यापारीकरण व अनेक मदों द्वारा छात्रों के शोषण को रोकने हेतु राष्ट्रीय कानून का अभाव भी इन आंकड़ों से सामने आता है। वर्तमान सरकारी नीतियां, कानून व केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के दावे उच्च शिक्षा में व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार को रो. कने की दृष्टि से खोखले व निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। अभाविप के 57 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का मानना है कि विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों (State University) की स्थिति दयनीय है व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में राज्यों के विश्वविद्यालयों में वित्त की भारी कमी है। विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा भी पर्याप्त वित्त व्यवस्था का अभाव है, एक तरफ हाल ही में खोले गये केन्द्रीय विश्वविद्यालय साधनों से सम्पन्न हैं तो दूसरी तरफ वर्षों से देशभर में सामान्य, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे यह विश्वविद्यालय घोर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, परिणाम स्वरूप वित्त व्यवस्था के नाम पर इन विश्वविद्यालयों में व्यापारीकरण स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने पैर पसार रहा है। सरकारें वित्त व्यवस्था से हाथ पीछे खींच रही है जिससे इन विश्वविद्यालयों के आधारभूत ढांचे का विकास रूक गया है, शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं एवम् शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। राज्यों द्वारा संचालित इन विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र–छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही छात्र उच्चतम शिक्षा या शोध कार्य हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। परिषद् का मानना है कि निरंतर सरकारी उपेक्षा व पर्याप्त साधनों के अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आयेगी एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभाविप 57 वें राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से यह मांग करती है कि केन्द्र सरकार ऐसे सभी विश्वविद्यालयों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज व

विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के वर्तमान अनुदानों में बढ़ोत्तरी करें।

अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देशभर के सामान्य महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की दयनीय स्थिति व गिरते शैक्षणिक स्तर पर भी चिन्ता व्यक्त करता है। देशभर के सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, अनु. जाति/अनु. जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्र तथा विशेष रूप से भारी संख्या में छात्राऐं इन महाविद्यालयों में अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसे में वित्त व्यवस्था के अभाव व लगातार सरकारों की उपेक्षा से शिक्षा के स्तर पर गिरावट आई है परिणामस्वरूप निजी शिक्षण संस्थानों को छात्रों का शोषण करने का अवसर मिला है। विद्यार्थी परिषद् केन्द्र व प्रदेश सरकारों से मांग करती है। कि ऐसे महाविद्यालयों हेतु अधिक बजट का प्रावधान किया जाये। विद्यार्थी परिषद् का यह भी मत है कि उपरोक्त शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के व्यक्तित्व विकास एवं उनमें देशभक्ति तथा सामाजिक दायियत्व बोध जागृत करने की दृष्टि से चलाए जाने वाले अनेक कार्यक्रम जैसे एन.सी.सी., एन. एस.एस., खेलकूद व युवा महोत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की वित्त अभाव के कारण उपेक्षित स्थिति बनी है, अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन उक्त गतिविधियों के लिये विशेष के प्रावधान करने तथा प्रतिभागियों के आर्थिक सहायता में वृद्धि की मांग करता है।

देश 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहा है। परिषद का यह स्पष्ट मत है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शोध कार्य में वृद्धि, शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने, सरकार के द्वारा अधिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोलने हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है अतः सरकार(GDP) में 6 प्रतिशत तथा कुल बजट 10 प्रतिशत का शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान करें।

अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा National Eligibility Entrance Test (NEET) को अगले दो वर्षों तक स्थगित करने के निर्णय का स्वागत करता है। परिषद् देश भर के छात्रों में भेदभाव रोकने व भाषा सम्बन्धित जटिलताओं को रोकने हेतु वर्तमान प्रणाली को यथावत बनाये रखने की मांग करती है तथा इस मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा की मांग करती है।

परिषद् का मानना है कि देशभर के छात्रों का महाविद्यालयीन शिक्षा में अनुपात बढ़ा है। देश की जनसंख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके विपरीत देशभर में सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना नही हुई है। विद्यार्थी परिषद् देशभर में नए सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना के साथ– साथ वर्तमान महाविद्यालयों की सभी सीटों में वृद्धि तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार हेतु विशेष प्रावधानों की मांग करती है। विशेष रूप से परिषद् दिल्ली सरकार से भी दिल्ली में बढ़ी छात्रों की संख्या के अनुपात में महाविद्यालय खोलने की मांग करती है। भारी जनसंख्या वृद्धि व देशभर के छात्रों का दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने के रूझान में वृद्धि हुई है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 12 वर्षों से एक भी नया महाविद्यालय नही खुला है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् देश में, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। दिल्ली में राधिका तंवर हत्याकाण्ड,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मे परीक्षा परिणाम के बदले असमत जैसे जघन्य कृत्य बलात्कार व छेड़छाड़ जैसी अनेक घटनाओं से देशभर में राजधानी की छवि धूमिल हुई है। इस सारे वातावरण में छात्राएं / महिलाएं स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती है, परिषद् इस अधिवेशन के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्यों की सरकारों से मांग करती है कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रयास व कानूनी पहल की जाये, छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय व विद्यालय स्तर पर किया जाय तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों में महिला विकास सेल स्थापित किये जाएं।

अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम से विकृत श्रीरामकथा को हटाने जाने का स्वागत करता है तथा इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों व अभाविप कार्यकर्ताओं के उग्र आन्दोलन की जीत मानता है।

अभाविप के इस पुनीत कार्य हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों का भी अभिनन्दन करती है। यह अधिवेशन विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम में विकृति श्रीरामकथा को पूर्व में समावेशित किये जाने को तथाकथित बुद्धिजीवियों के मानसिक दिवालियेपन और बौद्धिक छल का पर्याय मानता है, तथा इस कृतय के लिये तथाकथित बुद्धिजीवियों व उनके समर्थकों की घेर भर्त्सना करता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर देश के कई राज्यों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्रों को लोकतांत्रिक पद्धति से अपने प्रतिनिधि चुनने को अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभी भी देश के कई छात्र अपने इस अधिकार से वंचित है। विद्यार्थी परिषद् का यह 57 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन देश भर के विश्वद्यिालय व महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव तुरन्त करवाने की मांग करता है, परिषद् का मानना है कि पांच वर्ष पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित लिंगदोह समिति द्वारा छात्र संघ चुनाव की अनुशंसा की गई थी लेकिन अभी तक भी प्रदेश सरकारों व विश्वविद्यालयों ने चुनाव करवाने का प्रवधान नहीं किया है परिषद् इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानती है एवम् विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता को दूर रखने का षडयंत्र भी करार देती है। परिषद्, चुनावों या उच्चतम निर्णायक संस्थाओं (सिनेट/सिन्डीकेट/कार्यकारी परिषद) में छात्रों के सहभाग को सुनिश्चित किये जाने की मांग भी करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन उपरोक्त समस्याओं पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करती है तथा देशभर के छात्रों का शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को उठाने व देश में भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष का आह्वान करता है।

प्रस्ताव क्र. 2

देश का वर्तमान परिदृश्य

अभाविप के 57 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान केन्द्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते देश अराजकता की स्थिति से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार, घोटाले, कमरतोड़ महंगाई, देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा व गिरती विकास दर ने आम जनमानस को झकझोर के रख दिया है। ऐसे माहौल में केन्द्र में कांग्रेसनीत सरकार द्वारा अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में न लेते हुए थ्क् का प्रस्ताव लेकर आना, यह लोकतंत्र की धज्जियाँ उडाने वाला ही नहीं अपितु कांग्रेस की स्वेच्छाचारिता को भी दर्शाता है। संसद तथा देशभर में विरोध के दबाव के चलते यूपीए सरकार ने इसे रोक तो दिया है, लेकिन सरकार की मंशा व विदेशी दबाव के चलते एक बार फिर इसके आगे घुटने टेकने से इंकार नहीं किया जा सकता।

अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, USA के एक अध्ययन के अनुसार वहाँ वालमार्ट आने के बाद दस वर्षों में 555 किराने की दुकानें, 298 हार्डवेयर की दुकानें, 213 बि. ल्डिंग मटिरियल की दुकानें, 161 डिपार्टमेंट स्टोर, 158 महिला परिधान तथा 111 पुरूष परिधान की दुकानें, 153 जूतें की दुकानें और 116 दवाईयों की दुकानें बंद हो गई। भारत जैसे कृषि प्रधान और खुदरा व्यापार पर आधारित देश के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अतः यह राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से आह्वान करता है कि अधिकांश राजनैतिक पार्टियों समेत देश के सामान्य जन की भावनाओं को देखते हुए खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का यह प्रस्ताव वापिस ले और देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड न करें ।

गत कुछ वर्षों से दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई केन्द्र सरकार के इस विषय पर समग्र नीति के अभाव का ही नतीजा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा महंगाई नियंत्रण की गलत नीति के कारण देश की समृद्धि दर पर भी विपरीत असर पड़ा है। उधर वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं और इधर सांसदों व विधायकों के वेतन बार–बार बढ़ाये जा रहे हैं। गरीब अधिक गरीब हो रहा है और केन्द्र सरकार गरीब की परिभाषा में उलझ कर उसकी भावनाओं को आहत कर रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ।

सरकार की गलत नीतियां, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और बढ़ते कर्ज के कारण आज देश का किसान

बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को विवश है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सुयोग्य नीति के अभाव के कारण समाज तथा अर्थव्यवस्था का ध्वंस हो रहा है। यह 57 वां राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार को इस विषय में ध्यान देकर ठोस कदम उठाने की मांग करता है। देश के विभिन्न स्थानों में अवैध खनन में हो रही वृद्धि देश के लिए खतरे की घंटी है। इससे न केवल पर्यावरण को हानि पहुंच रही है बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है जिसका बुरा असर राजनीति तथा समाज पर पड़ रहा है।

दूसरी तरफ यूपीए–2 की भ्रष्टाचार में लिप्त व महंगाई नियंत्रण में असफल केन्द्र सरकार अपनी कारगुजारियों को छिपाने व मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते नए–नए हथकंडे अपना रही है। संसदीय परम्पराओं को ताक पर रखकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ;छ।ब्द्ध द्वारा लक्षित हिंसा बिल लाना व कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति करते हुए व्ठब् कोटे से 4.5 : अल्पसंख्यक आरक्षण देने का निर्णय मुस्लिम तुष्टीकरण व देश को बांटने का षड्यंत्र ही है। अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन इसकी घोर निंदा करता है और केन्द्र सरकार से यह मांग करता है कि उक्त दोनों निर्णयों को वापस लिया जाये अन्यथा देश का छात्र और समाज आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा।

वर्तमान में कश्मीर घाटी से अलगाववादियों द्वारा भसशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियमश ;।थ्ै।द्ध हटाने के बारे में उठ रही आवाज यह देश के लिए खतरा है, ऐसा अभाविप का मानना है। कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षाबलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ।थ्ै। को हटाने की मांग यह पाक प्रेरित तथा कश्मीर को देश से तोड़ने का षड्यंत्र है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश की एकता एवं अखंडता के लिए अभाविप मांग करती है कि ।थ्ै। को कायम रखा जाए। साथ ही लोकतंत्र के मंदिर – संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी अफजल गुरू की फांसी को माफ करने व एक विधायक द्वारा ।थ्ै। हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाने वाले जम्मू–कश्मीर सरकार की यह अधिवेशन कड़ी भर्त्सना करता है।

UID के बारे में अभाविप ने उसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को पत्र देकर देश की सुरक्षा समेत कई मुद्दों के बारे में आपत्ति उठाई थी। आज सरकारी स्तर पर भी इस विषय में कई आपत्तियाँ उठ रही हैं। इस योजना के लिए रूपये 1.40 लाख करोड़ जैसी बड़ी राशि का आवंटन बिना संसद के समक्ष लाते हुए करना संदेहास्पद है। यह 57 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को इसके लाभ से दूर रखा जाएँ तथा पूरी पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुधार करते हुए इस योजना की सार्थकता सुनिश्चित की जाएँ।

हाल ही में दिल्ली व मुंबई में हुए बम विस्फोट के तार एक बार फिर पाकिस्तानी एजेंसी ।ैप् के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकवादियों से मिली जानकारी ।ैप् के खतरनाक मंसूबों को जाहिर करती है। एक ओर पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा भारत में आंतरिक दहशत व अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है वही दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के पोषक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शांतिदूतश कहने की यह अधिवेशन निंदा करता है।

कई घटनाओं में वांछित कुख्यात् माओवादी किशनजी को मारकर सुरक्षा बल तथा पश्चिम बंगाल में नक्सल विरोधी संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसकी प्रतिक्रिया के तहत नक्सलियों द्वारा 8 जवानों की हत्या करना, पुलिस स्टेशन पर हमला करना दुखद है। इसके बाद भी कुछ तथाकथित मानवतावादियों के द्वारा किशनजी की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताने की यह राष्ट्रीय अधिवेशन निंदा करता है। अभाविप देश की जनता से आह्वान करती है कि नक्सल विरोधी लड़ाई में लगे हुए सुरक्षा बल तथा इसको सख्ती से निपटने के लिए कटिबद्ध राज्य सरकारों को समर्थन दे और इस लड़ाई को मजबूत बनाये।

पूर्वोत्तर में उग्रवादी भाक्तियों द्वारा 'बृहत् नागालैंड' की मांग करना किसी भी तर्क से देश हित में तथा समर्थनीय नहीं है। लोक दबाव के कारण भारत के प्रधानमंत्री ने उसे खारिज करके ठंडे बस्ते में तो डाल

दिया है लेकिन इस विषय में सरकार की भूमिका अभी भी संदेहास्पद है।

वर्तमान परिस्थिति में देश के समक्ष विविध प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए यह 57 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि देश हित में नीतियों को अवलम्ब करते हुए देश विरोधी ताकतों के साथ कठोरता से व्यवहार करते हुए यहाँ के आम आदमी का सुरक्षित, खुशहाल व सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव क्रं. 3

भ्रष्टाचार के विरूद्ध छात्रों एवं युवाओं का आह्वान

देश में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या पर चल रहे विभिन्न आन्दोलनों में अपनी हताशा और असहाय भाव को छोड़कर आम आदमी विशेषकर छात्र और युवा पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ एक बड़े बदलाव का स्वप्न मन में लिये सड़कों पर उतरा हैं तथा भ्रष्टाचारियों को निर्लज्जतापूर्वक बचाने का हर संभव प्रयत्न कर रही केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के दमनकारी कदमों को कड़ी चुनौती दी है। अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन उसका अभिनन्दन करता है ।

अभाविप ने 2010 में अपने बैंगलुरू अधिवेशन में "मौन तोड़ो, हल्ला बोलो" का नारा देकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपने संघर्ष का शंखनाद किया था जिसके पश्चात जनवरी 2011 के प्रारम्भ से ही धरना, प्रदर्शन, घेराव के देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ किये, जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर यूथ अगेंस्ट करप्शन मंच का उदय हुआ। भ्रष्टाचार के विरूद्ध विगत कई महीनों से यूथ अगेंस्ट करप्शन (वाईएसी) द्वारा देशव्यापी आन्दोलन चलाया जा रहा है। प्रदेश एवं जिला स्तरीय धरनों एवं प्रदर्शनों तथा देश के सभी जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी युवा सन्देश यात्राओं में लाखों छात्रों एवं युवाओं के साथ–साथ सामान्य जन द्वारा बढ़–चढ़कर भाग लेने से न केवल सम्पूर्ण देश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनता का एक तेवर बना है वरन् भ्रष्टाचार के विरूद्ध चल रहे अन्य आन्दोलनों को भी शक्ति व समर्थन मिला है तथा इन आन्दोलनों में यूथ अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी भी निभाई है जिससे देश की वर्तमान सरकार घबराई हुई है। अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन यूथ अगेंस्ट करप्शन के इन प्रयासों की सराहना करता है एवम् वाईएसी के अपने समर्थन के संकल्प को दोहराता है ।

भ्रष्टाचार का दीमक देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। वर्तमान यू.पी.ए.–2 के शासन में भ्रष्टाचार के मामलों एवं घोटालों की झड़ी लग गई है । देश का सामान्यजन चतुर्दिक भ्रष्टाचार, जो उसके रोजमर्रा के जीवन को दुष्कर बना चुका है, से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर आया है किन्तु केन्द्र की निर्लज्ज सरकार भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की बजाय भ्रष्टाचारियों को बचाने व भ्रष्टाचार के विरूद्ध उठने वाली आवाजों को सभी लोकतांत्रिक व मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर बर्बरतापूर्वक कुचलने का काम कर रही है ।

अन्ना हजारे व बाबा रामदेव द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनों को भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी यू.पी.ए. सरकार द्वारा कुचलने के कुत्सित प्रयासों की अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन घोर भर्त्सना करता है। सरकार ने राज्य सभा में लोकपाल बिल पर बहस के दौरान हंगामा कराकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के अपने कृत्य से संसदीय इतिहास को कलंकित करने का काम किया है ।

2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में सामने आये तथ्यों एवं दूरसंचार मंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री के बीच हुए पत्राचार से यह स्पष्ट हो गया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चि. दम्बरम भी इस घोटाले में बराबर के दोषी हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गये हाल के पत्र से भी इस बात की पुष्टि होती है। किन्तु बिना कोई जांच किये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पी. चि. दम्बरम को क्लीन चिट दिया जाना व पूरे मामले को सरकार के दो मंत्रियों के बीच का मामला बनाकर रफा–दफा करने की सरकार की कोशिश से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार अपना साराकौशल व शक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त अपने मंत्रियों व अपने सहयोगियों को बचाने में लगा रही है। अभाविप का

यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन वर्तमान गृह मंत्री पी0 चि. दम्बरम को 2जी स्पैक्ट्रम मामले में सह–अभियुक्त बनाने व उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार किये जाने की मांग करता है।

राष्ट्रमण्डल खेल घोटाले में दिल्ली सरकार की संलिप्तता पूरी तरह जगजाहिर है किन्तु दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरूद्ध लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बावजूद अभी कोई भी कार्रवाई आरम्भ नही की गयी। आदर्श सोसाइटी के घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गयी है किन्तु इस संदर्भ में किसी को भी अभी तक अभियुक्त नही बनाया गया है, न ही इस सिलसिले में किसी प्रकार की जांच आरम्भ की गयी है। संसद में सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए सांसदो की खरीद के मामले में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की बजाय इसको सामने लाने वालों (व्हिसल ब्लोअर्स) के विरूद्ध मामला बनाकर उल्टा उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकार की मिलीभगत से मुख्य आरोपी बनाये गये अमर सिंह को जमानत भी मिल गयी किन्तु सांसदों की खरीद से जिनको वास्तव में लाभ मिलना था उन तक पहुंचने का कोई प्रयत्न नही किया गया। रिलायंस ग्रुप को के.जी. बेसिन तथा विद्युत संयंत्र के लिए कोयला खदान आवंटन मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है जिससे देश को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रूपये की हानि हो रही है। इन सभी मामलों पर केन्द्र सरकार की निष्क्रियता की अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन घोर भर्त्सना करता है तथा दोषियों के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता है।

देश के लाखों–करोड़ रूपये काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा हैं। हाल के वर्षों में बदली वैश्विक परिस्थिति में ट्यूनीशिया और पेरू जैसे छोटे–छोटे देश भी विदेशों में जमा अपना काला धन वापिस लाने में सफल रहे हैं किन्तु केन्द्र की अब तक की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार इस काले धन को वापिस लाने की बजाय ऐसे खाताधारकों को बचाने में लगी हुई है। इसके लिए संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नये–नये बहाने बनाये जा रहे हैं । विदेशी सरकारों के साथ ऐसे समझौते किये जा रहे है जिससे अतीत के लुटेरों को बचाया जा सके । अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार से यह मांग करता है कि विदेशी बैंकों में जमा काले धन के धारकों की सूची तत्काल सार्वजनिक करे तथा कालेधन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा देश की धन–सम्पदा को अविलम्ब वापिस लायें एवं इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करें ।

देश में बुद्धिजीवियो एवं सामाजिक चिन्तकों में यह सर्वानुमति है कि भ्रष्टाचार के इतने विकराल स्वरूप और काले धन की इतने बड़े पैमाने पर व्याप्तता के मूल कारण के रूप में देश की वर्तमान धन आधारित चुनाव प्रणाली है। अतः भ्रष्टाचार से निपटने के लिए चुनाव सुधार अपरिहार्य हो गये हैं। अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि चुनाव सुधारों पर देशव्यापी बहस कराकर आगामी लोक सभा चुनाव सुधारों के साथ कराये जायें।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि दिन–प्रति–दिन सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों व घोटालों तथा निरन्तर विकराल रूप लेती काले धन की समस्या का समाधान भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी व कठोर कानून बनाकर एवं काले धन से निपटने के लिए पांच सौ व हजार रूपये के नोटों का चलन बन्द करके ही किया जा सकता है। आम आदमी को भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार से एक सक्षम व प्रभावी लो. कपाल व्यवस्था को लागू करने तथा इसी के साथ–साथ सार्थक न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, पुलिस सुधार एवं शैक्षिक सुधारों को भी लागू करने की मांग करता है ।

देश में अपनी जड़े जमा चुके व दिनोंदिन अपना व्याप बढ़ाते जा रहे भ्रष्टाचार के विरूद्ध अलग–अलग चलाये जा रहे आन्दोलनों से संघर्ष का वातावरण बना है। अभाविप का यह 57वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन भ्रष्टाचार के विरूद्ध देश की जनता के आक्रोश का सम्मान करता है तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चल रहे विभिन्न आंदोलनों को चला रहे आंदोलनकारियों व छात्रों और युवाओं से आह्वान करता है कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध काम कर रही यह सभी शक्तियां एक मंच पर आकर समवेत

आन्दोलन चलायें तथा भ्रष्ट केन्द्र सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके ।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् में पारित प्रस्ताव

चीन की बढ़ती आक्रमकता : शांति के लिये खतरा

चीन की अपने पड़ोसी देशों पर लगातार बढ़ती हुई आक्रामकता वर्तमान स्थिति में एशियाई क्षेत्रों को अस्थिर बना रही है। चीन की विस्तारवादी योजनाएँ तथा विशेषतः भारत के प्रति इसका आक्रामक रवैया इस क्षेत्र के लिये भारी खतरा बना है। अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति का दिखावा करके उसने अपने पड़ोसी देशों को सीमा विवाद के बहाने डराने और धमकाने के मार्ग पर बढ़ना शुरू किया है।

चीन का बढ़ता हुआ ढाँचागत विकास तथा सैन्य शक्ति की भारतीय सीमा पर बढ़ोतरी तिब्बत में आई.सी.बी.एम. की तैनाती तथा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 38वीं डिविजन की ताकत में बढ़ोतरी, 3000 से 4000 के लगभग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोगों की पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सीमा पर उपस्थिति तथा काराकोरम हाईवे का विकास और उसको पाक अधिकृत कश्मीर तथा इस्लामाबाद से जोड़ना बड़ी चिंताजनक बात है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नीतिगत भागीदारी भी चिंताजनक है। चीन, पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञान से युक्त कर रहा है और सैन्य तथा ढाँचागत क्षेत्र में उसके साथ सहभागिता बढ़ा रहा है। चीन का पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को सहयोग और उसके न्यूक्लियर शस्त्रों के फलने फूलने में चीन की भूमिका न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका, सिचलिस द्वीप तथा अन्य हिंद महासागरीय देशों को नाविक दल के अड्डे बनाकर "मोतियों की माला के रूप में" भारत को घेरने की चीन की नीति द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाने का एक सीधा उदाहरण है। अफ्रीका और मध्य एशिया में चीन की उपस्थिति एवं बढ़ती हुई ताकत भी चिंता का विषय है। अ.भा.वि.प. की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् भारत सरकार से मांग करती है कि वह इस मुद्दे पर सख्त दृष्टिकोण अपनाएँ और इस चुनौती से निपटने के लिये सर्वसमावेशक और सक्रिय नीति विकसित करें।

चीन की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल में ही 400 ऐसी घुसपैठ की घटनाएँ अरूणाचल प्रदेश और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र मे हुई है। चीन के द्वारा भारत के अरूणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों पर उसका अधिकार होने की बात बड़े जोरों से बताई जा रही है। गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मे एक चीनी पब्लिक सेक्टर कम्पनी द्वारा वितरित प्रपत्र में छपे मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश को चीन में अंतर्भाव किया गया था। शंघाई में एक प्रदर्शनी मे चीनी एजेंसियों ने भारत प्रदर्शनी पांडाल पर छापा मारकर अरूणाचल प्रदेश को भारत की सीमा में दर्शाने वाले मानचित्र जब्त किये। इन दोनों घटनाओं के बारे में भारत सरकार की आवाज बिलकुल क्षीण रही। भारतीय सैन्य शक्ति अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हुए भी भारत सरकार की चीन से निबटने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव एक समस्या है। अ.भा.वि.प. की रा. कार्यकारी परिषद् भारत के राजनैतिक समुदाय को आह्वान करती है कि चुनौती का सामना करने हेतु तत्पर हों।

चीन और भारत के बीच में रहा यू.एस. डॉलर 20 बिलियन का व्यापारी अनुशेष अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस असंतुलन को कम करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने के बजाय भारत चीनी माल का डम्पिंग यार्ड बन गया है। बी.एस.एन.एल. तथा कई अन्य संस्थाओं को चीनी तंत्रज्ञान सहयोगी तकनीक को अपनाना भी एक चिंता का विषय है। जिनका इतिहास संशय के घेरे में रहा है ऐसे हुवाई टेक्नोलॉजीस जैसे संस्थाओं से तंत्रवैज्ञानिक भागीदारी करना अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत के वियतनाम से जुड़े हित संबंधों के प्रति भी चीन विरोध दर्शा रहा है, जहाँ भारत साउथ चाइना सागर में ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड द्वारा दो तेल क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। चीन ने आई. एन. एस. एरावत के वियतनाम में शोध कार्यों को रोकने का भी प्रयास किया। दूसरी ओर चीन हिंद महासागर में

मिनरल का खनन करने का अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गया। लेकिन भारत सरकार की इन सबके प्रति प्रतिक्रिया निष्प्राणवत् रही है। अ.भा.वि.प. की रा. कार्यकारी परिषद् यह मांग करती है कि भारत सरकार अपने व्यापार क्षेत्र को आर्थिक आघातों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाये और हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित करें। भारतीय वस्तुओं के लिए चीनी मार्केट में अधिकाधिक प्रवेश मिलें इसके लिये भी सरकार को. शिश करें।

ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा हिमालय क्षेत्र की अन्य नदियों पर चीन के जल विद्युत तथा बड़े बांधों के प्रकल्प नीचले सतह वाले देशों भारत, वियतनाम, थाइलैंड, लाओस, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान पर बुरा परिणाम करेंगे। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् मांग करती है कि भारत सरकार इस मुद्दे को तुरंत निपटाए और देशहित का रक्षण करने हेतु तुरंत प्रभावी कदम उठाये। हिमालय क्षेत्र मे चल रहे ये चीन के प्रकल्प भविष्य में पानी की कमी की समस्या खड़ा करेंगे और भारत और चीन के बीच विवाद का प्रमुख कारण बन सकते हैं।

चीन की तानाशाही राजसता द्वारा मानवाधिकारों का उल्लघंन, अत्याचार और अनाचार के कारण उनकी अपनी जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ है। इसका चीनी राजशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तिब्बत में चीन द्वारा किया जा रहा मानवाधिकार का हनन तथा हाल ही में तिब्बती भिक्षुओं द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएँ भी चिंता का विषय है। परम पावन दलाई लामा की तरफ चीन का अपचन तथा उनके भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रवास करने पर चीन द्वारा जताई गई आपत्ति, उस देश द्वारा भारत के अंतर्गत व्यवहार में की गई अनावश्यक दखलदांजी है और इसे गंभीरता से निपटना होगा। अ. भा. वि. प. की रा. का. परिषद् यह मांग करती है कि भारत सरकार सभी संबंधित क्षेत्रों के बारे में एक कारगर नीति अपनाएं और चीन के साम्राज्यवादी रवैये से पीड़ित सभी एशियाई क्षेत्र के देशों को संगठित करके उनका नेतृत्व करें जिससे चीन के शक्ति वर्धन पर रोक लगाई जा सके। हमें ऐसा लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र होने के कारण भारत को एशियाई लोकतंत्रों को सक्षम बनाने तथा युरो–अमेरिकन जनतंत्रों के साथ संबंध विकसित करने हेतु नेतृत्व देना होगा। जिससे इस क्षेत्र में 'शांति और समृद्धि प्रस्थापित हो सके। साथ ही हम इस बात पर स्पष्ट रहें कि भारत की सीमा तिब्बत से सटी हुई है न कि चीन से। चीन द्वारा गैर कानूनी ढंग से तिब्बत पर अधिकार जताने से हमारी सीमाएं असुरक्षित हुई हैं और पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। तिब्बत के लोगों के अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और तिब्बत के गैर कानूनी अधिकरण का जल्दी से जल्दी अंत होना चाहिए।

हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के देशविघातक गुटों को तथा अन्य आंतरिक देश विघातक तत्वों को चीन द्वारा छुपे मार्ग से शस्त्रों को देने का भी भारत सरकार द्वारा गंभीरता के साथ निपटाना पड़ेगा। भारत सरकार और भारत की जनता को 1962 के आक्रमणों को भूलना नहीं चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि अभी भी अक्साई चिन, अरूणाचल प्रदेश का कुछ भाग और पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग कुल मिलाकर 63,180 कि.मी. क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में है। इसके साथ ही चीनी जनता को भी जानना चाहिए कि पड़ोसी के साथ शत्रुत्व और आक्रमण भाव रखने में उनके राष्ट्र का कोई दीर्घकालीन हित नहीं हो सकता। चीन और भारत की सभ्यताओं के बीच हजारों सालों से चले आये हुये सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुये वे दो बड़े शक्तिशाली देशों के बीच खड़ी कम्युनिस्टों के साम्राज्यवादी आक्रमण वृति को ठुकराकर क्षेत्र में समानता स्तर पर आधारित मित्रता के द्वारा शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करें। अ.भा.वि.प. भारतीय युवकों से अपील करती है कि वे चीन द्वारा खड़े किए हुए सभी आह्वानों को अपनी ताकतों के ऊपर उठने का अवसर समझकर और भारत को अधिक विकसित, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में कटिबद्ध हों।

गणित के जादूगर रामानुजन

महज 32 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए रामानुजन, लेकिन इस कम समय में भी वह गणित में ऐसा अध्याय छोड़ गए, जिसे भुला पाना मुश्किल है। अंकों के मित्र कहे जाने वाले इस जुनूनी गणितज्ञ की क्या है कहानी?

जुनून जब हद से गुजरता है, तो जन्म होता है रामानुजन जैसी शख्सियत का। स्कूली शिक्षा भी पूरी न कर पाने के बावजूद वे दुनिया के महानतम गणितज्ञों में शामिल हो गए, तो इसकी एक वजह थी गणित के प्रति उनका पैशन। सुपर–30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार की मानें, तो रामानुजन ने गणित के ऐसे फार्मूले दिए, जिसे आज गणित के साथ–साथ टेक्नोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है। उनके फार्मूलों को समझना आसान नहीं है। यदि कोई पूरे स्पष्टीकरण के साथ उनके फार्मूलों को समझ ले, तो कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से उसे पीएचडी की उपाधि आसानी से मिल सकती है।

अंकों से दोस्ती

22 दिसंबर, 1887 को मद्रास ख्अब चेन्नई, के छोटे से गांव इरोड में जन्म हुआ था श्रीनिवास रामानुजन का। पिता श्रीनिवास आयंगर कपड़े की फैक्ट्री में क्लर्क थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए वे सपरिवार कुंभकोणम शहर आ गए। हाईस्कूल तक रामानुजन सभी विषयों में अच्छे थे। पर गणित उनके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट की तरह था, जो धीरे–धीरे जुनून की शक्ल ले रहा था। सामान्य से दिखने वाले इस स्टूडेंट को दूसरे विषयों की क्लास बोरिंग लगती। वे जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की क्लास में भी गणित के सवाल हल करते रहते।

छिन गई स्कॉलरशिप

चमकती आंखों वाले छात्र रामानुजन को अटपटे सवाल पूछने की आदत थी। जैसे विश्व का पहला पुरुष कौन था? पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है? बेसिर–पैर के लगने वाले सवाल पूछने वाले रामानुजन शरारती बिल्कुल भी नहीं थे। वह सबसे अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए स्कूल में काफी लोकप्रिय भी थे। दसवीं तक स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप तो मिली, लेकिन अगले ही साल उसे वापस ले लिया गया। कारण यह था कि गणित के अलावा वे बाकी सभी विषयों की अनदेखी करने लगे थे। फेल होने के बाद स्कूल की पढ़ाई रुक गई।

कम नहीं हुआ हौसला

अब पढ़ाई जारी रखने का एक ही रास्ता था। वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इससे उन्हें पांच रुपये महीने में मिल जाते थे। पर गणित का जुनून मुश्किलें बढ़ा रहा था। कुछ समय बाद दोबारा बारहवीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन वे एक बार फिर फेल हो गए। देश भी गुलामी की बेड़ियों में कड़ा था और उनके जीवन में भी निराशा थी।

ऐसे में दो चीजें हमेशा रहीं–पहला ईश्वर पर अटूट विश्वास और दूसरा गणित का जुनून।

नौकरी की जद्दोजहद

शादी के बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए वे नौकरी की तलाश में जुट गए। पर बारहवीं फेल होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। बीमार हालात में जब भी किसी से मिलते थे, तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते। इस रजिस्टर में उनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। किसी के कहने पर रामानुजन श्री वी. रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहां पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में भी क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। यहां काम का बोझ ज्यादा न होने के कारण उन्हें गणित के लिए भी समय मिल जाता था।

बोलता था जुनून

रात भर जागकर वे गणित के नए–नए सूत्र तैयार करते थे। शोधों को स्लेट पर लिखते थे। रात को स्लेट पर चॉक घिसने की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती, पर आधी रात को सोते से जागकर स्लेट पर गणित के सूत्र लिखने का सिलसिला रुकने के बजाय और तेज होता गया। इसी दौरान वे इंडियन मैथमेटिकल सोसायटी के गणितज्ञों संपर्क में आए और एक गणितज्ञ के रूप में उन्हें पहचान मिलने लगी।

सौ में से सौ अंक

ज्यादातर गणितज्ञ उनके सूत्रों से चकित तो थे, लेकिन वे उन्हें समझ नहीं पाते थे। पर तत्कालीन विश्वप्रसिद्ध गणितज्ञ जी. एच. हार्डी ने जैसे ही रामानुजन के कार्य को देखा, वे तुरंत उनकी प्रतिभा पहचान गए। यहां से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होने 100 में 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए। लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में पूरे 100 अंक दिए थे।

उन्होंने रामानुजन को कैंब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैंब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। अपने एक विशेष शोध के कारण उन्हें कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए. की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन–सहन में वे ढल नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया।

अंतिम सांस तक गणित

उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। उन्हें रॉयल सोसायटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसायटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। और तो और, रॉयल सोसायटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। रॉयल सोसायटी की सदस्यता के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने।

करना बहुत कुछ था, लेकिन स्वास्थ्य ने साथ देने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर भारत लौटे। बीमार हालात में ही उच्चस्तरीय शोध–पत्र लिखा। मौत की घड़ी की टिकटिकी तेज होती गई। और वह घड़ी भी आ गई, जब 26 अप्रैल, 1920 की सुबह हमेशा के लिए सो गए और शामिल हो गए गौस, यूलर, जैकोबी जैसे सर्वकालीन महानतम गणितज्ञों की पंक्ति में।

महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष और हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।

वैश्विक है भारत की एकात्म शिक्षा प्रणाली

लक्ष्मीनारायण भाला

अभिमन्यु, महाभारत युद्ध के उस वीर का नाम है जो चक्रव्यूह भेद कर उस व्यूह-रचना से बाहर न आ पाने के कारण वीर-गति को प्राप्त हुआ। अपनी माँ के गर्भ में रहते समय ही उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात सुनी थी परंतु माँ के सो जाने के कारण व्यूह-रचना से बाहर निकलने की बात वह सुन नहीं पाया था। इस घटना की प्रामाणिकता आज के विज्ञान ने मान ली है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु माँ के आचरण से एवं अन्तर्बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है अतः व्यक्ति के जीवन का, उसके कर्तृत्व का, व्यक्तित्व का तथा तदर्थ आयोजित उसकी शिक्षा एवं संस्कार का विचार गर्भाधान से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर विश्व भर में प्रचलित विभिन्न शिक्षा व्यवस्थाओं की अपूर्णता को दूर करने के विचार से भारत में शिक्षा का एक प्रारूप प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र में शिशु-मनोविज्ञान के आधार पर कार्य करने वाली सर्वबृहत् शिक्षा संस्था 'विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान' के शिशु-वा. टिका विभाग ने अपनी योगधर्मिता के स्वभाव से इसमें पहल की है। अब हम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित करने या न करने के विवाद में उलझना छोड़कर भारत की शिक्षा व्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने का उद्यम प्रारंभ करें।

गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है अतः शिक्षा या विद्या का क्षेत्र भी जीवन व्यापी ही होना चाहिए। यही सोचकर गर्भाधान एवं गर्भावस्था यह केवल चिकित्सा क्षेत्र का विषय नहीं तो शिक्षा क्षेत्र का भी विषय है ऐसा विचार किया गया। संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है, जीवन भी अधूरा है इसी संदर्भ में हमारे मनीषियों ने कहा है कि 'जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते'। मनुष्य को शुद्रता से श्रेष्ठता की ओर ले जाना यह मूलतः शिक्षा एवं संस्कार के द्वारा ही संभव है। भारत के ऋषि मुनियों ने आध्यात्म एवं विज्ञान का समन्वय स्थापित कर गर्भाधान के पूर्व से लेकर अन्त्येष्टि के बाद तक मनुष्य जीवन का विचार करते हुए मूलतः सोलह संस्कारों की बात कही है। इन संस्कारों की चर्चा इस लेख का विषय नहीं है, यहाँ तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पर हम विचार करेंगे। इन अवस्थाओं में शिक्षा एवं संस्कार ग्रहण करने हेतु किन-किन क्रिया-कलापों एवं किस प्रकार के वातावरण या परिवेश की बात सोची जानी चाहिए इस पर भी विचार करेंगे। मनुष्य स्वयं के गर्भाधान एवं अन्त्येष्टि क्रिया का स्वयं साक्षी नहीं हो सकता परन्तु बीच की सभी अवस्थाओं का वह स्वयं साक्षी होता है। इस साक्षी जीवन का समग्रता से विचार करें तो गर्भावस्था, शिशु-अवस्था, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था इन सात अवस्थाओं के हम स्वयं साक्षी एवं शिल्पी होते हैं। इन सात अवस्थाओं का समग्रता से विचार करना हमारे लिए सहज-संभव है अतः उल्लेखित अवस्थाओं का सूत्र-बद्ध एवं एकात्म चिंतन करने पर निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं।

1. गर्भावस्था : मातृगर्भ में गर्भाधान के चार मास बाद गर्भस्थ शिशु के ज्ञानेन्द्रिय सक्रिय होने लगते हैं। अपनी संवेदनशीलता के कारण कर्णेन्द्रिय के द्वारा ध्वनी-तंत्र सक्रिय होकर सुनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भाषा शिक्षा के श्रवण, कथन, पठन, लेखन तथा सृजन इन पाँच पदों में प्रथम पद 'श्रवण' ही है। वह गर्भ माँ के द्वारा बोली गई भाषा सुनने लगता है। गर्भ के आंतरिक क्रियाकलापों के साथ बाहरी

वातावरण एवं क्रयाकलापों का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगता है। फलतः माँ के द्वारा सुनी गई बात भी वह सुनने लगता है। इसलिए गर्भावस्था की चिंता केवल चिकित्सा शास्त्र का विषय न होकर शिक्षा–शास्त्र का भी विषय बन जाता है। भाषा–शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था से माना जाना चाहिए। शुद्ध उच्चारण, मंत्रोच्चारण, संगीत एवं कथोपकथन की प्रक्रिया द्वारा गर्भ से संवाद स्थापित करने की कला से माँ को शिक्षित करना इसी अवस्था की आवश्यकता है।

2. शिशु–अवस्था : प्राणी जगत् में मनुष्य श्रेष्ठतम प्राणी होते हुए भी उसका शैशव अन्य प्राणियों की तुलना में दीर्घकाल तक 'असहाय' सा होता है। माँ, पिता, परिवार एवं चिकित्सकों द्वारा उसकी यथोचित देखभाल नहीं हो पाए तो उसका स्वस्थ एवं सम्यक विकास होना असंभव है। प्यार–दुलार तथा योग्य शिक्षा एवं संस्कार देने का प्रमुख कार्य मूलतः माँ को ही करना होता है अतः माँ ही उसकी प्रथम गुरु या शिक्षिका होती है। इन्द्रियों के क्रम–विकास के साथ–साथ उसकी क्षमताओं का भी विकास होने लगता है। लेटे रहने से, रेंगने, बैठने, खड़े होने, उछलकूद करने एवं चलने की क्षमता, सुनने, समझने एवं बोलने की क्षमता, वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने, उठाने, पटकने, तोड़ने, मरोड़ने, फाड़ने तथा यथास्थान रखने की क्षमता, खाद्य–अखाद्य को जानने, चूसने, चाटने, पीने, चबाने एवं खाने की क्षमता आदि कई प्रकार की क्षमताओं का क्रम–विकास उसकी अपनी अन्तः प्रेरणा से स्वयंस्फूर्त होती रहती है। मानसिक कल्पना एवं बौद्धिक कौतूहल आदि की क्षमता के विकास के कारण वह अनुकरण भी करने लगता है। परिणामतः इस आयु–वर्ग में उसके सम्पर्क में आने वाले हर व्यक्ति का आचरण स्नेह–प्रेम एवं सावधानी भरा होना चाहिए। 0 से 5 वर्ष के इस आयु वर्ग के लिए यही सूत्र सर्वमान्य होगा कि 'लालयेत पंचवर्षाणि' अर्थात् 5 वर्ष की आयु तक लालन–पालन हो।

3. बाल्यावस्था : 6 से 12 या 13 वर्ष तक की आयु मनुष्य–जीवन की सर्वाधिक ग्रहण–क्षमता की आयु होती है। इस आयु में केवल जानने–समझने की ही नहीं तो प्रत्यक्ष अनुभव करने की प्रबल इच्छा के कारण बालक क्रियाशील होने लगता है। इस क्रियाशीलता को केवल उत्पात या नटखटपन की संज्ञा देकर उसके क्रियाकलापों के प्रति उदासीन या कठोर होना, दोनों भी हानिकारक है। वास्तव में इस उम्र की हर गतिविधि को हमें संवेदनशील होकर सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, परखना एवं निर्देशित करना चाहिए। मन में उठी जिज्ञासा को शांत करना ही पर्याप्त नहीं तो नई जिज्ञासा को जगाना एवं बढ़ाना यह भी इस आयु की आवश्यकता है।

4. किशोरावस्था : 12 या 13 से 16–17 वर्ष की आयु का यह छोटा सा कालखण्ड मनुष्य जीवन का सबसे नाजुक तथा संवेदनशील कालखण्ड होता है। शारीरिक विकास के संधिक्षण के इस आयु में उसे स्वयं के स्त्री या पुरुष होने की अनुभूति होने लगती है। अवयवों के विकास के साथ–साथ मन में काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर एवं लोभ इन विकारों का अर्थात् षड्रिपुओं का प्रादुर्भाव भी प्रबलता से होता है। इस काल में सद्प्रवृत्तियों का जागरण अनिवार्य है अन्यथा उन्नति की ओर न जाकर जीवन प्रवाह पतन की ओर बढ़ेगा। योग–शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सृजनशीलता आदि क्रियाकलापों की सघनता हो तो उसका आचरण सदाचरण की ओर प्रवृत्त होगा। अतः इस आयु में मन के भावों को जानने, समझने या ताड़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही उक्त श्लोक में कहा गया है – दश वर्षाणि ताडयेत। बाल एवं किशोर अवस्था की यह ताड़ना या नियंत्रण रखना, नजर रखना, भविष्य के जीवन को सुयोग्य दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसी कालखंड में आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, संस्कारों, परम्पराओं तथा मान्यताओं को स्थापित करने की चिंता भी की जानी चाहिए।

5. युवावस्था : जीवन की सर्वाधिक कालावधि यौवन की ही होती है। 16–17 से 45 वर्ष तक हर व्यक्ति अपने आपको युवक समझता है। प्रायः 30 वर्ष तक

मनुष्य यौवनकाल का अनुभव लेता है। इस कार्यकाल मे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ अपने परिवार, समाज, देश एवं मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना यही आदर्श स्थिति कहलाएगी। यह स्थिति प्राप्त होने हेतु युवावस्था की प्रारंभिक स्थिति का गहन विचार मनीषियों ने किया है और कहा है कि 'प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्' पुत्र–पुत्रियों को मित्रवत् आचरण देकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना यह इस कालखंड का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा यह संभव नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा एवं स्वाध्याय इस समय की महती आवश्यकता है। ठोकरे खाने के बाद अक्ल आने की एवं शरीर शास्त्र के अनुसार अक्लदाढ़ आने की कालावधि भी यही है। हर देश का नागरिक अपने नागरिक धर्म को निभाते हुए अपना जीवन यापन करें यह युवावस्था का लक्ष्य एवं उद्देश्य होना स्वाभाविक है।

6. प्रौढ़ावस्था : युवावस्था के अनुभवों के आधार पर आयी हुई परिपक्वता ही प्रौढ़ावस्था है। सामान्यतः कर्ममय जीवन से अवकाश ग्रहण करने से पूर्व के 15 वर्ष एवं तत्पश्चात् 10 वर्ष अर्थात् आयु के 70 वर्ष की अवधि तक सामाजिक जीवन में आम व्यक्ति अपनी प्रौढ़ावस्था का अनुभव समाज में बाँटता रहता है। इस अवस्था के नागरिकों के अनुभवों का समाज–जीवन में अधिकाधिक लाभ हो एवं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य 'मोक्ष' की प्राप्ति का मार्ग भी सहज–सुलभ हो यही स्वस्थ समाज की पहचान है। यह स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने 'देह' एवं 'देव' के बीच के एक महत्वपूर्ण पड़ाव 'देश' का ध्यान रखते हुए अपने जीवन की रचना करता है। अपने अनुभवों का लाभ उपरोक्त पांचों अवस्थाओं के तबकों को मिलता रहे यह प्रौढ़ावस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है प्रौढ़ावस्था का नागरिक।

7. वृद्धावस्था : अपवाद के तौर पर 70 वर्ष की आयु के बाद भी सामाजिक कार्य में अगुवा रहने वाले, नेतृत्व देने वाले एवं सक्रिय रहने वाले कुछव्यक्तियों की बात छोड़ दी जाए तो आमतौर पर 70 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था की आदर्श स्थिति यही मानी जानी चाहिए कि अपने आँखों के सामने अपने किए कामों को सम्हालने वाले व्यक्तियों को हम स्वाधीन, स्वायत्त एवं सक्रिय रूप से योग्य दिशा में कार्य करते हुए देखें एवं अपने जीवन का संतोष एवं अपनी सफलता इसी में माने। मनुष्य जीवन की वृद्धावस्था कष्टदायी न होकर संतोषदायी एवं अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनी रहे यही समाज की आदर्श स्थिति है। यह स्थिति बनी रहने के लिए भारतीय मनीषियों ने हमें यह सूत्र सौंपा है–

अभिवादनशीलस्य नित्यम् वृद्धोपसेविने। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्यायशोबलम्।।

आयु–विद्या–यश एवं बल को बढ़ाने वाली शिक्षा एवं संस्कार के दो महत्वपूर्ण क्रिया कलाप या आचरण विधि है–अभिवादनशील होना एवं बड़े–बूढ़ों की सेवा करना। शिक्षा एवं संस्कार मानव जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं जो अभिन्न है, अविछिन्न है तथा अभेद्य है। शिक्षा एवं संस्कार की यह परम्परा भविष्य के किसी अभिमन्यु को अपूर्ण न रहने दे इसलिए माताओं को गर्भाधान से पूर्व ही सचेत करना एवं जागृत रखना यह आज के युग की महती आवश्यकता है। साथ ही मनुष्य के अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा भटकती न रह जाए इसलिए मोक्षदायी संस्कार व्यवस्था को समाज में निष्ठापूर्वक प्रतिष्ठित करना यह भी उतना ही आवश्यक है। धर्म–अर्थ–काम एवं मोक्ष का चिंतन करने एवं उन्हें प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाली यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति (व्यष्टि) के सर्वांगीण विकास के साथ उसके परिवार, समाज, (समष्टि) एवं सृष्टि के विकास तथा सुरक्षा की प्रक्रिया के साथ समन्वय स्थापित करने वाली है। आत्मा से परमात्मा (परमेष्टि) का संयोग स्थापित करने में सहायक होने वाली यह शिक्षा प्रणाली देश–काल निरपेक्ष शाश्वत् शिक्षा प्रणाली है। एकात्म मानव दर्शन के अन्तर्गत यह 'एकात्म शिक्षा प्रणाली' वैश्विक है, यह विश्व के लिए भारत की अनुपम देन है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

–: राष्ट्रीय पदाधिकारी–2011–12 :–

राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रा. मिलिंद मराठे ,ठाणे, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय महामंत्री

श्री उमेश दत्त ,दिल्ली

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री रविरंजन सेन, कोलकाता, प. बंगाल

डा. रघु अकमंची, हुबली, कर्नाटक

सुश्री ममता यादव, रेवाड़ी, हरियाणा

डॉ.विवेक निगम, प्रयाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश

डॉ. नरेंद्र सिंह, जम्मू–कश्मीर

राष्ट्रीय मंत्री

श्री श्रीरंग कुलकर्णी, दिल्ली

श्री सुरेंद्र नाईक, नागपुर, विदर्भ

सुश्री कृती पटेल, जबलपुर, महाकोशल

श्री कडीयम राजू, हैदराबाद, पश्चिम आंध्र

श्री रवि भगत, रायगढ़, छत्तीसगढ़

श्री विनय बिद्रे, शिमोगा, कर्नाटक

श्री अनिल कुमार, लखनऊ, मध्य उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय संगठन मंत्री

श्री सुनील आंबेकर, मुंबई, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री

श्री के. एन. रघुनंदन, बेंगलुरू, कर्नाटक

श्री सुनील बंसल, दिल्ली

राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

श्री लविन कोटीयन, मुंबई, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

श्री श्याम अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान

राष्ट्रीय सह कोषध्यक्ष

श्री महेश तेली, मुंबई, महाराष्ट्र

सुशासन दिवस 24 दिसंबर

जन अधिकारों की सुरक्षा का नया अध्याय

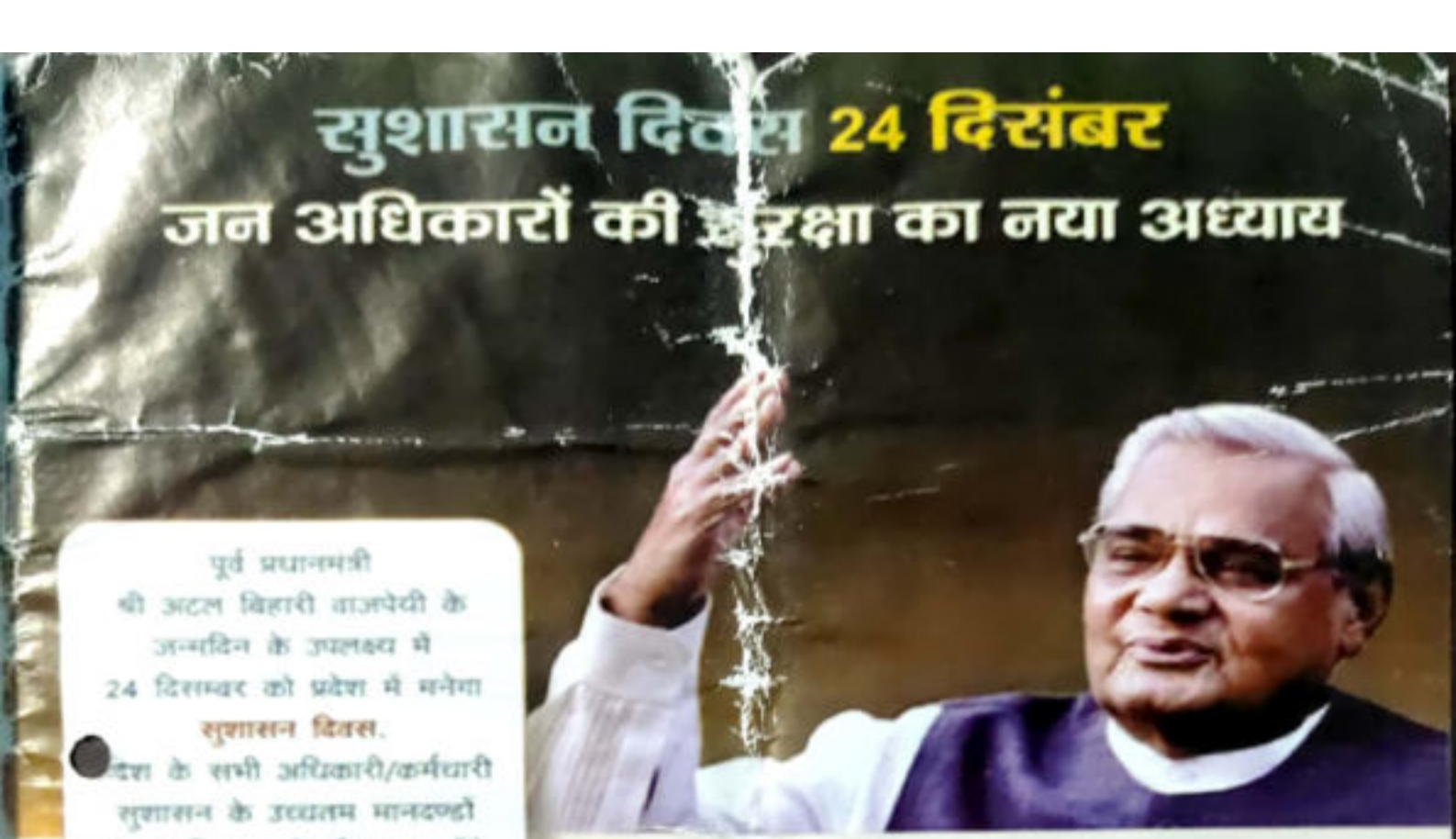

पूर्व प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में
24 दिसम्बर को प्रदेश में मनेगा
सुशासन दिवस.
प्रदेश के सभी अधिकारी/कर्मचारी
सुशासन के उच्चतम मानदण्डों
को स्थापित करने की शपथ लेंगे.

भारतीय राजनीति के पुरोधा, चिंतक, स्वप्नदृष्टा और मनीषी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन के उच्चतम मानदण्ड स्थापित किये. प्रदेश में उन्हें मूर्तरूप देने का कार्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं.

लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून

- पिछले एक वर्ष में बने इस कानून ने सुशासन को दी नयी दिशा.
- नियत समय में मिलती हैं ऐसी 52 सेवाएं जो रोज के कामों के लिए हैं जरूरी.
- तय समय में काम न होने पर जुर्माना.
- 80 लाख लोगों ने इस कानून का लाभ लिया.
- प्रदेश बना सुशासन क्षेत्र में मार्गदर्शक. देश के कई राज्यों ने भी प्रदेश की तरह कानून बनाए.

ऑनलाइन मॉनिटरिंग

- सुशासन के लिए अहम कदम है, कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग.
- ऑनलाइन माड्यूल से सुदृढ़ मॉनिटरिंग.
- हर माह के पहले मंगलवार को समाधान ऑनलाइन.
- समाधान - एक दिन और जनसुनवाई से नागरिकों से सीधा संवाद.

पारदर्शी प्रक्रिया

- कार्य पद्धति में पारदर्शिता, सुशासन की पहली जरूरत है. अब हुई नयी पहल.
- ई-टेंडरिंग.
- ठेकेदारों का सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन.
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान.
- भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया.
- वैज्ञानिक बजट व्यवस्था और समीक्षा.
- मैदानी अधिकारियों से सीधा संवाद.
- भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष न्यायालय विधेयक. भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जप्त कर उसे जनहित निर्माण में उपयोग का प्रावधान.

आइये,
संकल्प लें कि
प्रदेश में शासन को
पारदर्शी, सहभागी
और जनकल्याण
केन्द्रित बनायेंगे.

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

नागरिकों का हक, सुशासन

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आरएनआई नं० 32464/78

Con. No. - DL (N) / 249 / 10-12

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

57 वां राष्ट्रीय अधिवेशन

4–6 जनवरी 2012; नई दिल्ली

अधिवेशन सभागार में उपस्थित प्रतिनिधि

प्रदर्शनी उदघाटन करती श्रीमती पसरीचा

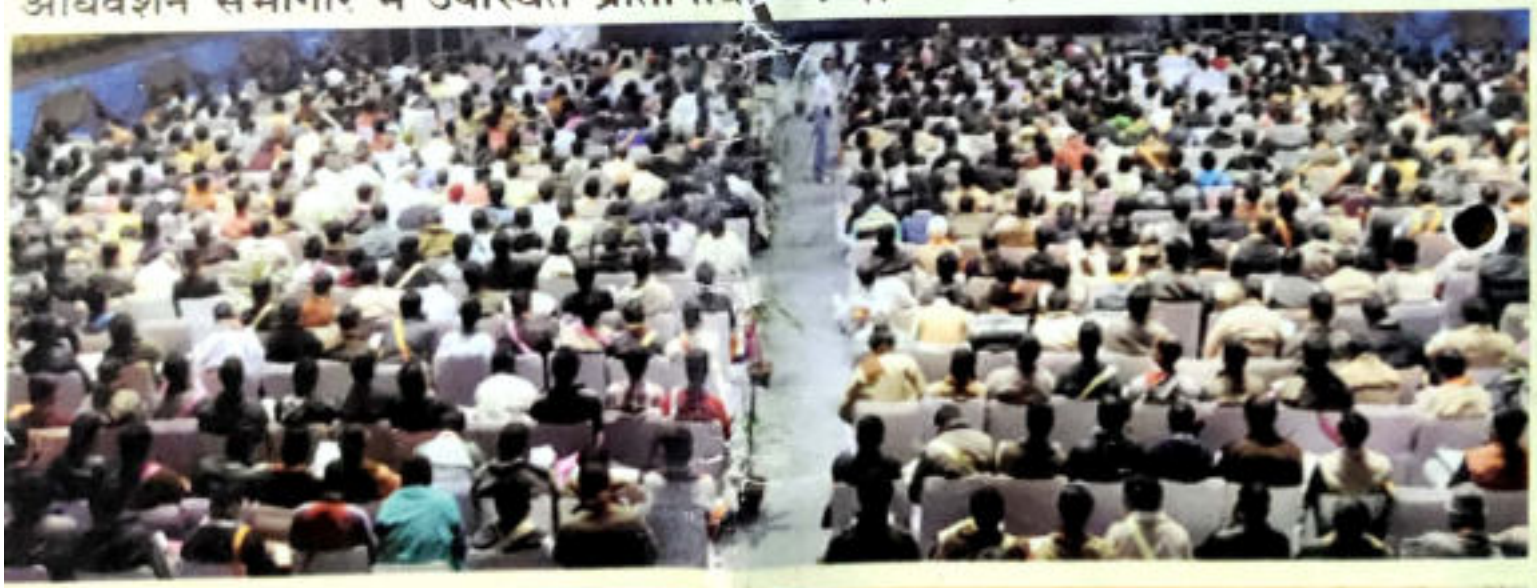

ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad